श्रावण कृष्ण पक्ष-प्रतिपदा, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-10, अंक-25 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल
30 जुलाई 2026 गुरुवार

आज का मौसम
28.7 अधिकतम
24.3 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

सरकार और किसानों के बीच फिलहाल टकराव टला लेकिन कसौटी पर रहेगी कृषि नीति

कंसाना के पत्र पर शिवराज के पलटवार से बदल गया मोहन सरकार का रुख

बड़ा सवाल ... क्या सरकार तभी सक्रिय होगी, जब किसान सड़कों पर आएंगे ?

नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन, विदिशा और नरसिंहपुर के ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसानों का दो दिन तक चला आंदोलन आखिरकार देर रात समाप्त हो गया। किसानों को मनाने के लिए डॉ. मोहन यादव सरकार को न केवल मूंग खरीदी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़े, बल्कि खरीफ सीजन के लिए खाद वितरण की विवादित टोकन व्यवस्था भी वापस लेनी पड़ी। दिलचस्प यह है कि यह पूरा घटनाक्रम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखे पत्र के तुरंत बाद सामने आया, जिसने पूरे विवाद को राजनीतिक रंग भी दे दिया।

प्रसंगवश
राजेश सिरोठिया

किसानों की नाराजगी केवल सरकारी खरीदी तक सीमित नहीं थी। एक ओर उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 8,776 रु प्रति क्विंटल के मुकाबले खुले बाजार में मात्र 5,000 से 5,500 रु प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा था, वहीं खरीफ की बुवाई के समय डीएपी खाद की कमी और एनपीके उर्वरक की कथित कालाबाज़ारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं। यही वजह रही कि हजारों किसान अपनी मांगों को लेकर राजधानी की सड़कों पर उतर आए।

ग्रीष्मकालीन मूंग मुख्यतः नर्मदापुरम संभाग के जिलों में उगाई जाती है। यह लगभग तीन महीने की फसल है और सिंचाई की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। कृषि विभाग के अनुसार इसका औसत उत्पादन लगभग 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दलहन उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार पीएम-आशा योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) संचालित करती है, जिसके तहत नेफेड और एनसीसीएफ राज्य की

सहकारी समितियों के माध्यम से खरीदी करते हैं।

इस वर्ष केंद्र सरकार ने देशभर में ग्रीष्मकालीन मूंग की 5,23,243 मीट्रिक टन खरीदी की स्वीकृति दी। इनमें से 4,54,580 मीट्रिक टन, अर्थात लगभग 87 प्रतिशत, अकेले मध्यप्रदेश को आवंटित किए गए। यह देश के किसी भी राज्य को मिला सबसे बड़ा हिस्सा है। तुलना करें तो उत्तर प्रदेश को 48,298 टन, गुजरात को 18,250 टन और हरियाणा को 2,115 टन की स्वीकृति मिली। इसके बावजूद मध्यप्रदेश में खरीदी की रफ्तार बेहद धीमी रही। 25 जुलाई तक केवल लगभग सात हजार टन और 29 जुलाई तक लगभग 60 हजार टन मूंग की ही खरीदी हो सकी। जबकि खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग 30 जुलाई तक और उपार्जन 10 अगस्त तक होना था। इसी धीमी गति ने किसानों में असंतोष को आंदोलन में बदल दिया।

इसी बीच प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त चार लाख टन मूंग खरीदी की अनुमति मांगी। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि पीएम-आशा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त अनुमति तभी दी जा सकती है, जब पहले से स्वीकृत मात्रा का अधिकांश उपार्जन पूरा हो जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में संकेत दिया कि जब राज्य अभी तक स्वीकृत मात्रा का बड़ा हिस्सा भी नहीं खरीद पाया है, तब अतिरिक्त कोटे की मांग का औचित्य समझ से परे है। इस पत्र के बाद पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया।

किसानों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा?

आंदोलन की असली वजह खरीदी की सीमा थी। किसानों का आरोप था कि जहां प्रति एकड़ पांच से छह क्विंटल तक उत्पादन हुआ, वहां सहकारी समितियां औसतन केवल लगभग 1.20 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग ही खरीद रही थीं। शेष उपज किसानों को खुले बाजार में औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ रही थी। जब सरकार का घोषित समर्थन मूल्य 8,776 रु प्रति क्विंटल हो और बाजार में केवल 5,000 से 5,500 रु का भाव मिले, तो किसान को प्रति क्विंटल 3,000 से अधिक का नुकसान उठाना पड़ता है। हजारों किसानों के लिए यही घाटा लाखों रुपये में बदल गया। यही आर्थिक अंतर आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बना।

केंद्रीय मंत्री के पत्र के बाद सरकार ने तेज की पहल

केंद्रीय कृषि मंत्री के पत्र के बाद राज्य सरकार ने तेजी से पहल की। मुख्यमंत्री ने स्वयं किसानों से मुलाकात नहीं की, लेकिन सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना और मंत्री कृष्णा गौर की समिति गठित कर उन्हें किसानों से बातचीत का जिम्मा सौंपा। देर रात तक चली वार्ता के बाद सरकार ने खरीदी की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि पर सहमति जताई। किसानों को अपनी उपज का लगभग 60 प्रतिशत तक सरकारी खरीदी में शामिल करने का आश्वासन दिया गया। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, खरीदी की अवधि भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया और खाद वितरण की विवादित टोकन व्यवस्था समाप्त करने पर भी सहमति बनी। हालांकि किसान अभी भी लगभग 63 प्रतिशत खरीदी की मांग पर कायम हैं।

खरीफ की सबसे बड़ी चिंता- खाद

मूंग के साथ किसानों की दूसरी बड़ी चिंता खरीफ की बुवाई है। डीएपी खाद की कमी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। किसानों का आरोप है कि लगभग 1,200 रु प्रति बोरी का एनपीके उर्वरक उन्हें 2,200 से 2,400 रु प्रति बोरी तक खरीदना पड़ रहा है। यदि इन शिकायतों में तथ्य हैं, तो यह केवल आपूर्ति व्यवस्था की समस्या नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक मजबूरी का भी प्रश्न है। सरकार ने टोकन व्यवस्था समाप्त कर आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर खाद वितरण का भरोसा दिया है। यदि यह निर्णय प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो खरीफ सीजन में किसानों को तत्काल राहत मिल सकती है।

सरकार की भी अपनी दलील

कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन मूंग में कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण उसके निर्यात में कठिनाई आती है। विभाग का दावा है कि पिछले वर्षों की बड़ी मात्रा में खरीदी गई मूंग अभी भी गोदामों में पड़ी है और उसके विपणन में समस्या आ रही है। हालांकि किसान संगठनों का इस दावे से स्पष्ट असहमति है। सिवनी मालवा के किसान नेता हरिशंकर कुशवाहा का कहना है कि किसान निर्धारित मात्रा से अधिक कीटनाशक का उपयोग नहीं करते। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिवकुमार शर्मा 'कक्का जी' का कहना है कि यदि सरकार को वास्तव में ग्रीष्मकालीन मूंग की गुणवत्ता पर संदेह है, तो उसे वैज्ञानिक परीक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। यदि फसल सुरक्षित नहीं है, तो उसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए; और यदि सुरक्षित है, तो किसानों को संदेह के आधार पर नुकसान नहीं उठाना चाहिए।

मौजूद हैं कई गंभीर सवाल ...

मूंग आंदोलन भले फिलहाल समाप्त हो गया हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल छोड़ दिए हैं। यदि केंद्र पहले ही देश की कुल स्वीकृत खरीदी का 87 प्रतिशत मध्यप्रदेश को दे चुका था, तो किसान एमएसपी से तीन हजार रुपये से अधिक कम दाम पर अपनी उपज बेचने को क्यों मजबूर हुए? यदि खाद वितरण व्यवस्था में खामियां थीं, तो उन्हें समय रहते क्यों नहीं सुधारा गया? और यदि ग्रीष्मकालीन मूंग की गुणवत्ता पर सरकार को गंभीर आपत्तियां हैं, तो उसके वैज्ञानिक प्रमाण सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? सरकार और किसानों के बीच तत्काल टकराव भले टल गया हो, लेकिन इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश की कृषि नीति और राजनीतिक जवाबदेही, दोनों की परीक्षा लेते रहेंगे। सवाल केवल मूंग खरीदी का नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार किसानों की शिकायतों पर तभी सक्रिय होगी, जब वे राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे और मामला राजनीतिक दबाव का विषय बन जाएगा?

दिलीप गावित की रिकॉर्ड दौड़, भारत को तीसरा गोल्ड

ग्लासगो। दिलीप महादु गावित ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सातवें दिन भारत को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने पुरुषों की पैरा टी47 कैटेगरी में100 मीटर रेस में 10.71 सेकेंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। भारत के ही मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकेंड के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि इंग्लैंड के केविन सैंटोस ने 10.85 सेकेंड के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया। टी47 कैटेगरी में उन ट्रैक एथलीट्स को शामिल किया जाता है, जिनके एक या दोनों हाथों में शारीरिक अक्षमता होती है। इसमें हाथ के किसी हिस्से की कमी या हाथ की कार्यक्षमता प्रभावित होने वाले खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

रहाणे का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, बोले- अब नया पड़ाव

मुंबई। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी-20 खेल चुके रहाणे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। रहाणे ने कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने का यही सही समय है। रहाणे ने वीडियो में कहा, जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और अंत भी होता है। जब समय आता है, तो हमें बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है।

न्यूज विंडो

अमेरिका का ईरान के 10 से ज्यादा शहरों पर हमला

वॉशिंगटन डीसी/ तेहरान। अमेरिका ने सुबह ईरान में 10 से ज्यादा शहरों पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केश्म, किश, काजेरून, अहवाज, अबादान, शादेगान, अरवंदकेनार, बुशेहर, जाम और खोरमोज को निशाना बनाया गया है। केश्म द्वीप पर रिहायशी इमारत पर हमले में एक दंपती और उनके 2 साल के बच्चे की मौत हुई, जबकि दो अन्य बच्चे घायल हुए।

बिलासपुर में दोहरे हत्याकांड का दोषी जेल में गर्म भट्ठी में कूदा

बिलासपुर। केंद्रीय जेल में दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ने भोजन बनाने वाले गैसीफायर प्लांट की गर्म भट्ठी में कूदकर जान दे दी। जेल परिसर के भीतर बुधवार शाम 4.15 बजे कूदे कैदी का शव बाहर नहीं निकाला जा सका था। अब भट्ठी के ठंडे होने के बाद आज शव निकाला जाएगा। जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी ने बताया कि जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह निवासी राहुल उर्फ विकेश कंवर दोहरी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

बलराम महोत्सव

सीएम ने किसानों को वितरित की मुआवजा राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुरहानपुर में आयोजित 'बलराम महोत्सव' कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित किया और सिंगल क्लिक के जरिए फसल नुकसान से प्रभावित किसानों के खातों में मुआवजा राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रही है और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे।

दतिया उपचुनाव

दोपहर 1.30 बजे तक 45 फीसदी वोटिंग

दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। सुबह से मतदाताओं में उत्साह बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों समेत कई मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें देखने को मिलीं। दोपहर 1.30 बजे तक 45 फीसदी मतदान हो चुका था।

मतदान शुरू होने से पहले तीन मतदान केंद्रों पर ईवीएम से जुड़े उपकरणों में तकनीकी खराबी आई, जिन्हें मॉक पोल के दौरान सभी एजेंटों और कैमरों की मौजूदगी में बदल दिया गया। मतदान केंद्र क्रमांक 186 पर वीवीपैट, क्रमांक 108 पर बैलेटिंग यूनिट (बीयू) और क्रमांक 290 पर कंट्रोल यूनिट (सीयू) में खराबी आई थी। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सभी उपकरण समय रहते बदल दिए गए।

भारी बारिश.. केदारनाथ ट्रैकिंग रूट बंद

असम में बाढ़ के हालात का दृश्य।

भोपाल/जयपुर/लखनऊ। देशभर में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान समेत 16 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के तीन जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में गुरुवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ ट्रैकिंग रूट बंद कर दिया गया है और तीर्थयात्रियों को रोका गया है।

हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में गंगाजल भरते समय युवक बहने लगा। घाट पर ड्यूटी कर रही एसडीआरएफ टीम ने उसे बचा लिया। वहीं, रुद्रप्रयाग में सिल्ली के पास मलबा आने से हाईवे कुछ देर बाधित रहा, जबकि पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक कार दब गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी का कटाव तेज हो गया है। पानी गांवों में घुस गया है।

असम में कहीं दरिया बना तो कहीं टापू, अब तक 78 मौत

असम में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. शिवसागर और गोलाघाट में तीन और मौतों के साथ बाढ़ से मरने वालों की संख्या 78 पहुंच गई है। राज्य के सात जिलों में 3 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी 21 राजस्व सर्कल और 551 गांवों तक पहुंच गया है, 21,523.08 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न हो गया है।

छात्रों की पिटाई और चढ़ावा चोरी पर संसद परिसर में प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने आज सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। उन्होंने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। प्रियंका गांधी प्रदर्शन में शामिल हुईं। लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर ही चल सकी और दो बजे तक के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में आज दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पेश किया जाएगा।

आज का कार्टून

मेट्रो एंकर

भस्म आरती के लिए देर रात से ही लगी लाइन, मंदिर परिसर में खास इंतजाम

सावन की पहली सुबह... महाकाल के दरबार में उमड़ी अपार श्रद्धा

उज्जैन, दोपहर मेट्रो

देवों के देव महादेव को समर्पित पवित्र श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है। सावन के पहले ही दिन धार्मिक शहर उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लग गया है। भोलेनाथ के प्रिय इस महीने में दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु देर रात से ही मंदिर परिसर और आसपास जुटने लगे थे। अलसुबह ठीक 3 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए, जिसके बाद शुरू हुई ऐतिहासिक भस्मआरती में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए।

मान्यता है कि सावन महीने में शिव आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रावण के पहले दिन महाकाल मंदिर में विशेष अनुष्ठान और परंपराओं का दौर चला। भस्मआरती से ठीक पहले बाबा महाकाल को पवित्र जल से नहलाया गया और इसके बाद दूध, दही, घी, शहद व विभिन्न फलों के रसो से उनका भव्य पंचामृत अभिषेक किया गया। भांग और चंदन से भोलेनाथ का मनमोहक श्रृंगार कर उन्हें वस्त्र पहनाए गए। आरती में भस्म चढ़ने के बाद जब बाबा निराकार से साकार रूप में आए, तो पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया है। कतार प्रबंधन, सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा सहायता और पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों की भी तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकें। पंजाबी गायक दीप मनी भी महाकाल मंदिर पहुंचे और विशेष पूजा-अर्चना में भाग लिया। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन को बेहद शांतिपूर्ण और दिव्य अनुभव बताया।

दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग

महाकाल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत केंद्र भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल महाकालेश्वर की विशेषता यह है कि यहां भगवान शिव दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं, जिसे अत्यंत दुर्लभ और विशेष महत्व का माना जाता है। श्रावण मास के दौरान बाबा महाकाल की पारंपरिक सवारी भी विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। हर सोमवार को भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। चांदी की पालकी में विराजमान बाबा का विभिन्न स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है और हजारों श्रद्धालु मार्ग में पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत करते हैं। आने वाले पूरे महीने महाकाल की नगरी देशभर के शिवभक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी रहेगी।

बारिश के बाद खिल उठा भोपाल का बड़ा तालाब, प्रकृति ने ओढ़ी हरियाली की चादर

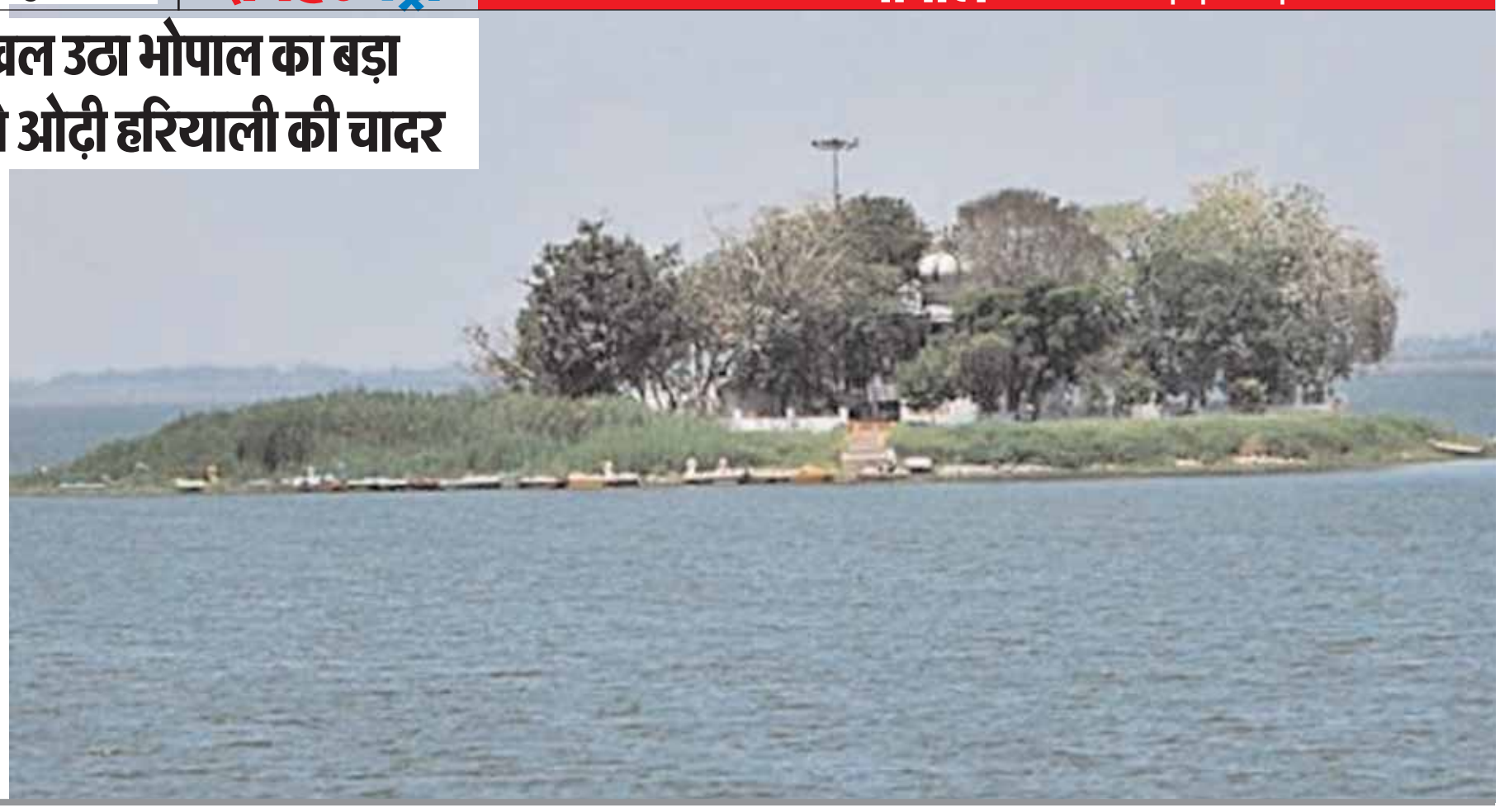

भोपाल. दोपहर मेट्रो। मानसून की झमाझम बारिश के बाद राजधानी का बड़ा तालाब एक बार फिर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ दमक उठा है। तालाब के बीचों-बीच स्थित छोटा-सा टापू हरियाली की चादर ओढ़े किसी प्राकृतिक स्वर्ग से कम नहीं दिख रहा। नीले आसमान की छांव, लहरों पर पड़ती धूप की चमक और शांत जलराशि के बीच तैरती छोटी-छोटी नावें इस दृश्य को और भी मनमोहक बना रही हैं। बारिश ने न केवल तालाब का जलस्तर बढ़ाया है, बल्कि आसपास की हरियाली में भी नई जान फूंक दी है। यही वजह है कि बड़ा तालाब इन दिनों भोपालवासियों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुबह-शाम यहां पहुंचने वाले लोग प्रकृति के इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद करने के साथ सुकून के पल भी बिता रहे हैं। मानो मानसून ने झीलों की नगरी भोपाल को फिर से अपनी प्राकृतिक पहचान और ताजगी से भर दिया हो।

एनजीटी ने छह सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट

अकबरपुर में अवैध खुदाई पर राज्य सरकार और कलेक्टर समेत चार विभागों को नोटिस

भोपाल, दोपहर मेट्रो

कोलार रोड स्थित अकबरपुर बाघ भ्रमण क्षेत्र में पहाड़ी कटान, अवैध खुदाई और पेड़ों की कटाई के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने मध्यप्रदेश शासन, भोपाल कलेक्टर, नगर निगम, वन विभाग और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

सर्वे नंबर-3 स्थित सरकारी भूमि पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों से लगातार पहाड़ी काटकर समतल की जा रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में हरे-भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगा। दानिश हिल्स व्यू कॉलोनी के रहवासियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और मशीन संचालकों से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। एनजीटी ने माना कि संबंधित क्षेत्र बाघों के विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां मोर, हिरण सहित कई वन्यजीवों का नियमित आवागमन रहता है। अधिकरण ने कहा कि भारी मशीनों से हो रही खुदाई और शोर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका भी बढ़ सकती है। मामले की जांच के लिए कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि की दो सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की गई है। समिति छह सप्ताह में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की गई है।

इस लिए संवेदनशील है अकबरपुर का बाघ क्षेत्र

कोलार रोड के निकट स्थित अकबरपुर क्षेत्र वन्यजीवों की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। यह इलाका बाघों के भ्रमण और विश्राम क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। यहां मोर, हिरण, सियार और अन्य वन्यजीवों का नियमित आवागमन रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी कटान, अवैध खुदाई और भारी मशीनों के लगातार संचालन से वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित होता है। इससे वन्यजीव सुरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष का खतरा बढ़ने की आशंका रहती है। एनजीटी ने मामले को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए दो सदस्यीय संयुक्त जांच समिति गठित की है। समिति में भोपाल कलेक्टर के नामित प्रतिनिधि और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल रहेंगे। समिति स्थल का निरीक्षण कर यह जांच करेगी कि खुदाई और पहाड़ी कटान वैध अनुमति से हुआ या नहीं तथा पर्यावरण और वन्यजीवों को कितना नुकसान पहुंचा। जांच रिपोर्ट के साथ आवश्यक कार्रवाई का विवरण भी छह सप्ताह के भीतर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

रहवासियों ने की कार्रवाई की मांग

अकबरपुर बाघ भ्रमण क्षेत्र में कथित अवैध खुदाई और पहाड़ी कटान का मामला तब सुर्खियों में आया, जब स्थानीय रहवासियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की। इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने स्वतः संज्ञान लिया। यह मामला दर्शाता है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर मीडिया की सक्रियता न्यायिक हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।

आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती

कल सील होंगी 800 से अधिक दुकानें और शोरूम, नगर निगम के नोटिस से हंगामा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राजधानी में आवासीय अनुमति लेकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई तेज हो गई है। निगम ने अब तक 800 से अधिक दुकानदारों और शोरूम संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के 429 व्यापारियों को 15 जून और 17 जुलाई को नोटिस दिए गए थे, जिनकी समय-सीमा पूरी होने के बाद बुधवार से उनकी दुकानों और शोरूम पर सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो सकती है।

मामले को लेकर व्यापारियों में बेचैनी है, जबकि अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के रहवासी कार्रवाई की उम्मीद लगाए हुए हैं। दरअसल, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है। इससे पहले राज्य सरकार न्यायालय में जवाब की तैयारी कर रही है। अरेरा कॉलोनी के रहवासियों का आरोप है कि पिछले दो दशकों से आवासीय भूखंडों पर होटल, शोरूम और अन्य व्यवसाय संचालित होने से शोर, ट्रैफिक और अव्यवस्था बढ़ी है। वहीं व्यापारी पक्ष का कहना है कि वे जीएसटी, कमर्शियल बिजली, गुमास्ता

लाइसेंस और अन्य सभी वैध शुल्क जमा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अवैध नहीं माना जा सकता। नगर निगम के अनुसार नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि तय समय में नियमों का पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। इस बीच रहवासियों ने एक अगस्त से 'सिटिजन वॉक' निकालकर इस मुद्दे पर जनजागरण अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है।

अरेरा कॉलोनी के रहवासी पिछले दो वर्षों से आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिहायशी भूखंडों पर होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य व्यवसाय चलने से क्षेत्र की शांति भंग हो रही है। शोर, ट्रैफिक, पार्किंग और प्रदूषण से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इसी मुद्दे पर अरेरा कॉलोनी निवासी पूर्णेंदु शुक्ला ने कानूनी लड़ाई शुरू की। मामला हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग के संबंध में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही नगर निगम ने नोटिस जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।

व्यापारी बोले- हम नियमों का पालन कर रहे

नोटिस मिलने के बाद व्यापारी संगठनों ने नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वे वर्षों से कमर्शियल बिजली कनेक्शन, जीएसटी पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस और अन्य सरकारी करों का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अवैध बताकर प्रतिष्ठान सील करना उचित नहीं है। व्यापारियों का तर्क है कि इन प्रतिष्ठानों से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

मेट्रो ट्रेन के लिए जमीन ली, मुआवजा नहीं दिया, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

भोपाल/जबलपुर, दोपहर मेट्रो

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने मध्यप्रदेश प्रशासन से दो सप्ताह के भीतर पूरी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि तय समय में स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो भोपाल कलेक्टर को स्वयं अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।

मामला भोपाल निवासी जाकिर अली खान और जाहिदा बी की अलग-अलग याचिकाओं से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण कई साल पहले कर लिया गया, लेकिन अब तक नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। पीड़ितों का कहना है कि वे लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि जमीन मालिकों को मुआवजा मिला या नहीं? यदि भुगतान लंबित है तो इसकी वजह क्या है? कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित करने के बाद समय पर मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि अब तक की गई कार्रवाई, मुआवजा भुगतान की स्थिति और देरी के कारणों की विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए कई लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। प्रभावित जमीन मालिकों का आरोप है कि प्रशासन ने जमीन तो ले ली, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें उनका अधिकारिक मुआवजा नहीं मिला।

ऑनलाइन लघुकथा गोष्ठी में बोले घनश्याम मैथिल

'लघुकथा को परिपक्व होने का समय दें, तभी निखरेगा सृजन'

भोपाल, दोपहर मेट्रो

वरिष्ठ लघुकथाकार एवं समीक्षक घनश्याम मैथिल 'अमृत' ने कहा कि लघुकथा लिखने, उसके परिपक्व होने और प्रकाशित होने के बीच लेखक को पर्याप्त समय और संयम रखना चाहिए। अपने लिखे को बार-बार पढ़ने से हर बार उसमें सुधार की नई संभावनाएँ सामने आती हैं। वे लघुकथा शोध केंद्र समिति, भोपाल द्वारा आयोजित साप्ताहिक ऑनलाइन लघुकथा गोष्ठी एवं विमर्श में मुख्य समीक्षक के रूप में विचार व्यक्त कर रहे थे।

कार्यक्रम में कोलकाता

(पश्चिम बंगाल) की सुप्रसिद्ध लघुकथाकार चंदा प्रहलादिका ने 'भूख', 'सम्मान', 'धोखा', 'सुकून' तथा 'भूख और इंसानियत' जैसी लघुकथाओं का प्रभावी वाचन किया। इन रचनाओं में मानवीय लालच, दिखावे, विश्वासघात, टूटते वैवाहिक संबंधों और मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखा गया।

कार्यक्रम का संचालन अश्विनी देशपांडे (दिल्ली) ने किया। समिति की निदेशक कांता रॉय ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। लघुकथाओं पर पदम गोधा, साकार श्रीवास्तव, विधु भूषण मंडल और अनीता रश्मि ने समीक्षात्मक टिप्पणियाँ दीं। अंत में चंदा प्रहलादिका ने सभी साहित्यकारों एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी में देशभर के अनेक लघुकथा लेखक और पाठक ऑनलाइन उपस्थित रहे।

मेट्रो एंकर बीयूएमएस की उर्दू पुस्तकों का हिंदी अनुवाद तैयार, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा मप्र

उर्दू के साथ अब हिंदी में भी होगी यूनानी डॉक्टर बनने की पढ़ाई

भोपाल, दोपहर मेट्रो

भोपाल। करियर की राह में भाषा अब बाधा नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां यूनानी चिकित्सा (बीयूएमएस) की उर्दू पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत भोपाल स्थित प्रदेश के एकमात्र शासकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय से इसी शैक्षणिक सत्र में होगी। पहले वर्ष की सभी आवश्यक पुस्तकों का हिंदी अनुवाद तैयार हो चुका है।

दरअसल, वर्ष 2022-23 के बाद भारत सरकार ने प्रवेश नियमों में बदलाव करते हुए बीयूएमएस में प्रवेश के लिए दसवीं में उर्दू विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद गैर-उर्दू भाषी

विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2025-26 में 75 सीटों में से 15 विद्यार्थियों ने, जबकि 2024-25 और 2023-24 में सात-सात गैर-उर्दू भाषी छात्रों ने प्रवेश लिया। इन्हें पढ़ाई में भाषा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आयुष विभाग का मानना है कि हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध होने से अधिक विद्यार्थी यूनानी चिकित्सा की ओर आकर्षित होंगे। इससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की भागीदारी भी बढ़ेगी तथा डॉक्टरों के रिक्त पद भरने में आसानी होगी। उल्लेखनीय है कि एमबीबीएस की पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही रहा है। शासकीय यूनानी कॉलेज की प्राचार्य प्रो. (डॉ.) महमूदा बेगम ने बताया कि प्रथम वर्ष की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद पूरा हो चुका है और इन्हें इसी सत्र से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

क्यों लिया गया हिंदी अनुवाद का फैसला

यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई वर्षों से उर्दू भाषा में उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से होती रही है। प्रवेश नियमों में बदलाव के बाद बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी बीयूएमएस में आने लगे हैं, जिन्होंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी। ऐसे छात्रों को विषय समझने में कठिनाई होती थी। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम वर्ष की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद कराया है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई आसान होगी और भाषा के कारण प्रतिभाशाली छात्र पीछे नहीं रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यूनानी चिकित्सा शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

2500 साल पुरानी है चिकित्सा पद्धति

यूनानी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान (ग्रीस) में हुई थी। बाद में इसका विकास अरब देशों और फारस में हुआ तथा 11वीं-12वीं शताब्दी में यह भारत पहुंची। भारत सरकार ने इसे आयुष प्रणाली के तहत मान्यता दी है। यह चिकित्सा पद्धति शरीर के चार द्रव—रक्त, कफ, पीत पित्त और श्याम पित्त—के संतुलन पर आधारित है। उपचार में आहार, औषधि, मालिश, भाप और व्यायाम का विशेष महत्व होता है। मध्य प्रदेश में भोपाल का एक शासकीय और इंदौर, देवास तथा बुरहानपुर में तीन निजी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय संचालित हैं।

त्विषा शर्मा मौत मामला

सीबीआई को 11 अगस्त तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

भोपाल. दोपहर मेट्रो। मॉडल से एक्ट्रेस बनीं त्विषा शर्मा मौत मामले में भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी है। मंगलवार को दोनों आरोपित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अतिरिक्त समय की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि प्रकरण की जांच अंतिम चरण में है और कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

7 अगस्त से गांव-गांव पहुंचेंगे अफसर, कलेक्टरों से दो टूक बोले सीएस

जन विश्वास अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दें सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राज्य सरकार के प्राथमिकता वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत 7 अगस्त से होगी। इससे पहले मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने प्रदेशभर के कलेक्टरों, संभागायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बतौर मुख्य सचिव पहली बार कलेक्टरों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वार्ड और पंचायत स्तर पर इकाइयां बनाकर शिविर से एक सप्ताह पहले क्षेत्र की समस्याओं और लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि अभियान के दौरान लोगों को त्वरित राहत मिल सके।

अभियान की तैयारियों के दिए निर्देश- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर, संभागायुक्त, जिला पंचायतों के सीईओ और अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने कहा कि वार्ड और पंचायत स्तर पर इकाइयां बनाकर शिविर आयोजित किए जाएंगे। संबंधित क्षेत्रों में शिविर से पहले लंबित समस्याओं और नागरिकों के आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई पूरी की जाए। उन्होंने अभियान को परिणाम आधारित बनाने पर जोर दिया।

हर शुक्रवार करेंगे योजनाओं की समीक्षा- मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को संभाग और जिला स्तर के अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी योजना के लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया जाएगा।

आम जनता से होगा सीधा संवाद

अभियान के तहत अधिकारियों का पहला कार्यक्रम आम जनता से संवाद होगा। संबंधित गांव या क्षेत्र के सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई के लंबित मामलों की जानकारी साझा की जाएगी तथा नए आवेदन भी लिए जाएंगे। कार्यक्रम यथासंभव सरकारी भवनों के परिसर में आयोजित किए जाएंगे। संभागायुक्त भी प्रत्येक शुक्रवार को संभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। भ्रमण के दौरान स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र, उचित मूल्य की दुकान समेत अन्य सरकारी संस्थानों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अधिकारियों को हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

पोर्टल से होगी मॉनिटरिंग

मुख्य सचिव ने बताया कि अभियान की मॉनिटरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। लंबित आवेदनों के निराकरण के आधार पर जिलों का मूल्यांकन होगा। जिन मामलों में बजट या राज्य स्तर पर निर्णय की जरूरत होगी, उन पर संभागायुक्त विभागीय प्रमुखों से समन्वय करेंगे। अभियान के दौरान जनसंवाद के साथ उद्योग संवाद भी आयोजित होगा, जिसमें एमएसएमई और अन्य उद्यमियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

इन मामलों का भी होगा निराकरण

अभियान के दौरान अविवादित नामांतरण, बंटवारा, खसरे में सुधार, फार्मर आईडी, आधार, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन समेत अन्य लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। शिविर की तिथि तय होने के बाद संबंधित क्षेत्र के लंबित प्रकरणों का पहले से समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खाद-बीज के गोदाम, गैस गोदाम और पेट्रोल पंपों का निरीक्षण भी अभियान का हिस्सा होगा।

मुख्यमंत्री बोले- एमपी में जल्द 1000 के करीब होंगे बाघ

वन्यजीव संरक्षण हमारी प्राथमिकता घड़ियालों के संरक्षण के हो रहे प्रयास

भोपाल, दोपहर मेट्रो

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में बाघ संरक्षण का अग्रणी राज्य है। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में 785 बाघ थे और आगामी गणना में यह संख्या एक हजार के करीब पहुंचने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वी पर यदि कहीं बाघ इंसानों के सबसे नजदीक रहते हैं तो वह भोपाल और उसके आसपास का क्षेत्र है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार नदियों में घड़ियालों का संरक्षण भी कर रही है। पहले घड़ियालों का लाभ राजस्थान को अधिक मिलता था, लेकिन अब प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में छोड़े गए घड़ियाल यहीं सुरक्षित रहें।

मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल पूजा-पाठ का पर्व नहीं, बल्कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला उत्सव है। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से विश्वगुरु की अवधारणा पर चलता आया है और प्रकृति के प्रति सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का उदाहरण देते हुए कहा कि पेड़ों में प्राण होने की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से स्वीकार की जाती रही है।

ओरछा के लक्ष्मी मंदिर की सराहना

डॉ. यादव ने ओरछा स्थित माता महालक्ष्मी मंदिर की भव्यता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार के सभी विभाग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वन विभाग के साथ काम करने में उन्हें सबसे अधिक आनंद आता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों के साथ वन्यजीवों के आदान-प्रदान की पहल भी की है। हाथियों के कारण होने वाली जनहानि को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कार्यक्रम में वन बल प्रमुख शुभरंजन सेन ने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व हमेशा वन्यजीव संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा जंगल वही माना जाता है, जहां बाघ, बाघिन और उनके शावक सुरक्षित हों। बाघों का संरक्षण प्रकृति और मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

वाहनों का लोकार्पण, प्रदर्शनी का अवलोकन और सम्मान समारोह

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए नए वाहनों का लोकार्पण किया तथा वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभागीय प्रकाशनों का विमोचन, सक्रिय वन्यजीव प्रबंधन पर आधारित वृत्तचित्रों के टीजर जारी किए और राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के पद्मश्री सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन किया। इस अवसर पर वन सुरक्षा समितियों, ईको विकास समितियों, ग्राम वन समितियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया गया।

मध्य प्रदेश में कम बारिश का असर

हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन गिरकर एक चौथाई हुआ, 30% बढ़ी बिजली की मांग

गांव के इलाको में दिखा सीधा असर, बिना बताए पावर कट की दिक्कत है

जबलपुर, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में इस साल कम बारिश का सीधा असर प्रदेश के पावर सेक्टर पर पड़ा है। बारिश कम होने से जहां एक तरफ बिजली की मांग में करीब 30 फीसदी की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ हाइडल पावर का जनरेशन घटकर लगभग एक-चौथाई रह गया है। वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर , मुंबई) की रिपोर्ट के आधार पर यह आंकड़े रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर और एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने जारी किए हैं।

एक साल में 3,000 मेगावॉट से ज्यादा बढ़ी मांग

जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में बिजली की ज्यादा से ज्यादा मांग और कुल खपत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 28 जुलाई 2025 को प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग 10,395 मेगावॉट थी, जो 28 जुलाई 2026 को बढ़कर 13,471 मेगावॉट पर पहुंच गई। यानी महज एक साल में मांग में 3,076 मेगावॉट की बढ़ोतरी हुई। वहीं, पिछले साल 28 जुलाई को 22 करोड़ 32 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई थी। जो इस साल बढ़कर 28 करोड़ 74 लाख यूनिट हो गई। इसमें करीब 30 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है।

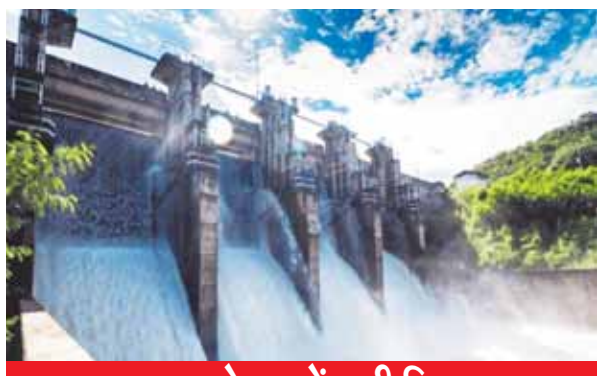

पावर जनरेशन में भारी गिरावट

कम बारिश के कारण बांधों और जलाशयों में पानी कम होने से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल 28 जुलाई को जल विद्युत परियोजनाओं से 4 करोड़ 93 लाख यूनिट बिजली बनी थी। इस साल 28 जुलाई को यह उत्पादन गिरकर महज 1 करोड़ 17 लाख यूनिट रह गया, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग एक-चौथाई (25त) ही है।

महंगी बिजली खरीदने को मजबूर, जनता पर पड़ेगा बोझ- हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में आई इस भारी कमी की भरपाई करने के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय क्षेत्र की कंपनी NTPC से अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है। पिछले साल NTPC से 77 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी गई थी। इस साल यह खरीद दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 180 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह महंगी दर पर अतिरिक्त बिजली खरीदने का सीधा आर्थिक बोझ MP की आम जनता पर ही पड़ेगा।

ग्रामीण इलाकों में बिना बताए पावर कट का आरोप

राजेंद्र अग्रवाल ने आरोप लगाया है- मांग और आपूर्ति में अंतर के कारण प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी बिजली की खरीद, आपूर्ति और कटौती से जुड़े आंकड़े खुद सार्वजनिक करे, ताकि जनता के सामने असली तस्वीर साफ हो सके।

भोपाल के अकबरपुर बाघ भ्रमण क्षेत्र में अवैध खुदाई पर एनजीटी सख्त

सरकार-कलेक्टर सहित चार पक्षों को नोटिस

भोपाल, दोपहर मेट्रो

कोलार रोड स्थित अकबरपुर बाघ भ्रमण क्षेत्र में पहाड़ी कटान, अवैध खुदाई और पेड़ों की कटाई के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कलेक्टर, नगर निगम, वन विभाग और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने यह नोटिस नवदुनिया में नौ जुलाई को ÷बाघ भ्रमण क्षेत्र अकबरपुर में पहाड़ी को उजाड़ रहे थे भूमाफिया, रहवासियों ने किया विरोध...÷ शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वत- संज्ञान लेकर जारी किए हैं।

एनजीटी ने आदेश में बताया कि समाचार के अनुसार, रहवासियों ने आरोप लगाया गया था कि सर्वे नंबर-तीन, अकबरपुर की सरकारी भूमि पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों से लगातार खुदाई कर पहाड़ी को समतल किया जा रहा है तथा बड़ी संख्या में हरे-भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दानिश हिल्स व्यू कालोनी के रहवासियों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और हंगामा किया। मशीन संचालकों से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई वैध सरकारी अनुमति नहीं दिखाई गई।

अधिकरण ने कहा कि संबंधित क्षेत्र बाघों के विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां मोर, हिरण सहित अन्य वन्यजीवों का नियमित आवागमन रहता है। लगातार खुदाई, पहाड़ी कटान और भारी मशीनों के शोर से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

एनजीटी ने पर्यावरण से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना

एनजीटी ने प्रथम दृष्टया माना कि मामले में पर्यावरण से जुड़ा गंभीर प्रश्न उठता है। इसके बाद मध्यप्रदेश शासन, भोपाल कलेक्टर, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल नगर निगम और वन विभाग को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी किया है। मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की है, जिसमें कलेक्टर और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति को मौके का निरीक्षण कर छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक एवं कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान को मिली वैश्विक पहचान

भोपाल। मप्रदेश में संचालितनशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा नशामुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से संचालित इस अभियान को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। अभियान के अंतर्गत बड़वानी एवं बुरहानपुर जिलों में विद्यार्थियों की अभूतपूर्व सहभागिता ने न केवल जन-जागरूकता का नया आयाम स्थापित किया है, बल्कि प्रदेश को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित भी किया है।

इंदौर में दूषित पानी से बढ़ा बीमारी का खतरा

नर्मदा लाइन से आ रहा है काला पानी; रहवासी पीने के लिए बाजार से पानी खरीदने को मजबूर

इंदौर, दोपहर मेट्रो

मूसाखेड़ी क्षेत्र की अजय बाग कॉलोनी के रहवासी पिछले दो माह से दूषित पेयजल की समस्या का सामना कर रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि नर्मदा जल सप्लाई वाले दिन नलों से शुरुआती 15 से 20 मिनट तक काला और बदबूदार पानी निकलता है। पानी से सीवेज जैसी दुर्गंध आती है, जिसके कारण लोग इसे घरेलू उपयोग में लेने से भी डर रहे हैं। उनका कहना है कि दूषित पानी के कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है और कई लोग बीमार भी हो चुके हैं।

कॉलोनी के अधिकांश परिवार पीने के पानी के लिए नर्मदा जल सप्लाई पर निर्भर हैं। हालांकि कुछ घरों में बोरिंग की सुविधा है, लेकिन दूषित पानी आने से कई परिवारों को बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है। रहवासियों ने सीएम हेल्पलाइन और नगर निगम के 311 एप पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि बिना समाधान किए शिकायतों का निराकरण दिखा दिया गया।

श्रम संहिताओं के मसौदा पेश करने के लिए समिति गठित

भोपाल, दोपहर मेट्रो

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत म.प्र शासन, श्रम विभाग द्वारा समुचित सरकार के रूप में चार राज्य नियमों को लागू किया जाना है। श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश वेतन संहिता नियम 2026, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध नियम 2026, मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियम 2026 और मध्यप्रदेश उपजीविका जन्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा नियम 2026 राज्य नियमों के प्रारूपतैयार किये गये हैं।

27 जुलाई 2026 को आयोजित वरिष्ठ सचिव समिति द्वारा उपरोक्त प्रारूप नियमों का सूक्ष्मता से परीक्षण एवं अध्ययन करने के लिये एवं नियमों को अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के लिये राज्य शासन द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठनश्री अमित राठौर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर की अध्यक्षता में किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में श्री जॉन किंग्सली सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन को सदस्य बनाया गया है। श्री रघुराज राजेन्द्रन सचिव श्रम को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।

समिति के समक्ष श्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप नियमों पर श्रमायुक्त द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। समिति द्वारा प्रारूप नियमों का अनुमोदन किए जाने के उपरांत उन्हें वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। समिति द्वारा प्रारूप नियमों का विवरण 7 दिवस के भीतर श्रम विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

मेट्रो एंकर | मध्यप्रदेश में नौकरी की राह आसान करेगा एईडीपी

डिग्री के साथ मिलेगा उद्योगों में काम का अनुभव, 84 का चयन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत मध्यप्रदेश में शुरू किया गया अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) अब रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा का मजबूत मॉडल बनता जा रहा है। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री के साथ-साथ उद्योगों में काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी मिलता है।

एईडीपी के पहले बैच के 84 विद्यार्थियों का विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हुआ है। वहीं, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अब तक इस कार्यक्रम में 3500 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। विभाग को उम्मीद है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक यह संख्या लगभग 5000 तक पहुंच सकती है।

एईडीपी में विद्यार्थियों को पारंपरिक पढ़ाई के साथ उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यक्रम के शुरुआती दो वर्षों में विषय आधारित अध्ययन के साथ विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमता विकसित की जाती है। अंतिम वर्ष में उन्हें संबंधित क्षेत्रों की कंपनियों में अप्रेंटिसशिप का अवसर मिलता है।

इस दौरान विद्यार्थी वास्तविक कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन्हें नियमानुसार स्टाइपेंड भी दिया जाता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम वर्ष का मूल्यांकन किया जाता है। इससे डिग्री पूरी होने तक विद्यार्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता के साथ उद्योग का अनुभव भी होता है।

वर्ष 2024 में एईडीपी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पहला बैच अब अप्रेंटिसशिप के लिए तैयार हो चुका है। चयन प्रक्रिया में रिटेल ऑपरेशंस के 21 विद्यार्थियों का चयन लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है।

विद्यार्थियों में बढ़ रहा भरोसा

एईडीपी के प्रति विद्यार्थियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 बैच के 963 विद्यार्थी वर्ष 2026 में अप्रेंटिसशिप के लिए पात्र हो चुके हैं। वहीं, 2025-26 सत्र में 4513 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया था। वर्तमान सत्र में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी एईडीपी से जुड़ रहे हैं। उद्योगों के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए इस सप्ताह करीब 110 विद्यार्थियों के साक्षात्कार विभिन्न कंपनियों में आयोजित किए जा रहे हैं।

कई क्षेत्रों में उपलब्ध हैं पाठ्यक्रम

एईडीपी के तहत बीकॉम में बीएफएसआई, रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स और ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशंस जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा बीएससी हेल्थकेयर मैनेजमेंट और बीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं। एईडीपी का उद्देश्य युवाओं को केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल और रोजगार के लिए तैयार बनाना है। यही वजह है कि यह कार्यक्रम मध्यप्रदेश में विद्यार्थियों की नई पसंद बनता जा रहा है।

बराबरी की अधूरी नींव

किसी भी राष्ट्र की आर्थिक यात्रा में कुछ आंकड़े उत्साह जगाते हैं और कुछ प्रश्न खड़े करते हैं। भारत में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सकल कुल आय घोषित करने वाले उद्यमियों की संख्या का चार वर्षों में 142 से बढ़कर 576 हो जाना ऐसा ही एक आंकड़ा है। यह निस्संदेह बताता है कि देश में उद्यमिता का विस्तार हुआ है, पूंजी का प्रवाह बढ़ा है और व्यापार के लिए वातावरण पहले की तुलना में अधिक अनुकूल बना है। लेकिन हर चमकती हुई उपलब्धि के पीछे एक ऐसा आईना भी होता है, जिसमें विकास का दूसरा चेहरा दिखाई देता है। यही वह क्षण है, जब आंकड़ों की तालियों के बीच समाज की खामोशियों को भी सुनना आवश्यक हो जाता है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार, रक्षा उत्पादन, बुनियादी ढांचे में निवेश और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी नीतियों ने उद्योग जगत को नई ऊर्जा दी है। जीएसटी, डिजिटल भुगतान प्रणाली और कारोबारी प्रक्रियाओं में सुधार ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। ऐसे वातावरण में बड़े उद्योगों का विस्तार होना और सफल उद्यमियों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक भी है। यह उस आर्थिक आत्मविश्वास का संकेत है, जिसे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अर्जित किया है। सफल उद्योगपति किसी भी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं। वे निवेश करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, नई तकनीक लाते हैं और सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। इसलिए केवल इस आधार पर कि अमीर लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसे नकारात्मक परिघटना नहीं कहा जा सकता। संसद में प्रस्तुत आंकड़े जहां नई आर्थिक शक्ति का संकेत देते हैं, वहीं वैश्विक असमानता रिपोर्ट-2026 एक अलग तस्वीर भी सामने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की केवल एक प्रतिशत आबादी के पास देश की लगभग 40 प्रतिशत संपत्ति है। आय के स्तर पर भी शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय आय का 58 प्रतिशत अर्जित करती है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों के हिस्से केवल 15 प्रतिशत आय आती है। यह अंतर केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और अवसरगत असमानता की कहानी भी कहता है।

रिकॉर्ड एफडीआई ने साबित किया... क्यों है दुनिया का भारत पर भरोसा !

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
स्तंभकार

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर वर्षों से अनेक तरह के राजनीतिक आरोप लगाए जाते रहे हैं। कभी कहा जाता है कि विदेशी निवेशक भारत से दूर जा रहे हैं, कभी यह दावा किया जाता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण वैश्विक कंपनियों का भरोसा टूट रहा है, किंतु इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दावों को संसद में प्रस्तुत ताजा आंकड़ों ने नकार दिया है। क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 94.84 अरब डॉलर के सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का नया रिकॉर्ड बनाया है। यह इस बात का प्रमाण है कि दुनिया के बड़े निवेशक भारत को भरोसेमंद और सबसे अधिक संभावनाओं वाले देशों में मान रहे हैं।

वस्तुतः राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े आज बताते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में जहां सकल एफडीआई 80.61 अरब डॉलर था, वहीं अगले ही वर्ष यह बढ़कर 94.84 अरब डॉलर हो गया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नेट एफडीआई भी 0.96 अरब डॉलर से बढ़कर 6.95 अरब डॉलर पहुंच गया है। इसका अर्थ यह है कि विदेशी निवेशकों का वास्तविक भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नेट एफडीआई में पहले जो गिरावट दिखाई दी थी, उसका प्रमुख कारण निवेशकों द्वारा लाभ लेकर पूंजी वापस ले जाना और भारतीय कंपनियों का विदेशों में तेजी से निवेश करना था। अर्थात भारत से पूंजी का बाहर जाना आर्थिक कमजोरी न होकर यह भारतीय उद्योगों के वैश्विक विस्तार का संकेत है।

मोदी सरकार के दौर में निवेश को किया प्रोत्साहित भारत ने वर्ष 2014 के बाद विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। रक्षा और रेलवे का क्षेत्र हो या बीमा, नागरिक उड्डयन, कोयला अथवा अंतरिक्ष, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, सिंगल-ब्रांड रिटेल और डिजिटल सेवाओं के साथ विनिर्माण जैसे अनेक क्षेत्र, इन सभी में एफडीआई नियमों को उदार बनाया गया।

इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, जीएसटी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और व्यापार सुगमता में सुधार जैसे अनेक कदमों ने भारत को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया। कहना होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यकाल में भारत ने कई वर्षों तक 70 से 85 अरब डॉलर के बीच एफडीआई आकर्षित किया और अब 2025-26 में लगभग 95 अरब डॉलर का नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। वस्तुतः यह दर्शाता है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है।

किन देशों ने भारत पर सबसे अधिक भरोसा जताया?: मोदी सरकार के दौरान भारत में आने वाले एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत लगातार सिंगापुर रहा है। इसके बाद मॉरीशस का स्थान आता है, जोकि लंबे समय से भारत में निवेश का प्रमुख माध्यम रहा है। इनके अतिरिक्त जिन देशों ने भारत में उल्लेखनीय निवेश किया है, उनमें अमेरिका, नीदरलैंड, जापान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, केमैन द्वीप समूह प्रमुख हैं। हाल के वर्षों में यूएई के साथ हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के बाद वहां से निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जापान ने औद्योगिक कॉरिडोर, मेट्रो रेल, ऑटोमोबाइल और हाई-टेक विनिर्माण में भारी निवेश किया है, जबकि अमेरिका की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत को अपने भविष्य के डिजिटल केंद्र के रूप में देख रही हैं। केवल सेवाएं नहीं, अब विनिर्माण भी आकर्षण का केंद्रसंयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की नवीनतम विश्व निवेश रिपोर्ट बताती है कि भारत सेवा क्षेत्र तक सीमित निवेश गंतव्य से आगे बढ गया है। अब यहां इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, अक्षय ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स और उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण में भी विदेशी कंपनियां तेजी से निवेश कर रही हैं। यही कारण है कि भारत ने वैश्विक एफडीआई रैंकिंग में दो स्थानों की छलांग लगाकर 13वें से 11वें स्थान पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। ग्रीनफील्ड निवेश में भी दुनिया का विश्वासवर्ष 2025 की सबसे बड़ी घोषित ग्रीनफील्ड परियोजना भारत में आई। अमेरिका की Alphabet Inc. ने लगभग 14.5 अरब डॉलर के डेटा सेंटर निवेश की घोषणा की। यह परियोजना निश्चित तौर पर भारत के डिजिटल भविष्य पर वैश्विक विश्वास का प्रतीक है। इसी प्रकार पोलैंड की Hynfra ने आंध्र प्रदेश में लगभग 4 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। हरित ऊर्जा, हाइड्रोजन और औद्योगिक अवसंरचना के क्षेत्र में ऐसे निवेश भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं।

भारतीय कंपनियां भी बन रही हैं वैश्विक खिलाड़ीमोदी सरकार ने आंकड़ों के आधार पर यह भी बताया है कि वर्ष 2022 में लागू उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नियमों के बाद भारतीय कंपनियां विदेशों में तेजी से विस्तार कर रही हैं। टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदाणी समूह, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, सन फार्मा, महिंद्रा समूह और अन्य भारतीय कंपनियां विश्व के अनेक देशों में निवेश बढ़ा रही हैं। वस्तुतः यह प्रवृत्ति बताती है कि भारत अब विदेशी निवेश लेने, उसे आमंत्रित करने के साथ वैश्विक निवेश करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था भी बन रहा है। निवेशक लाभ कमा रहे हैं, इसलिए लौट भी रहे हैंविपक्ष अक्सर विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी वापस ले जाने को भारत से विश्वास समाप्त होने का संकेत बताता है, जबकि आर्थिक दृष्टि से इसका दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। जब निवेशक अच्छा लाभ कमाते हैं तो वे अपने मुनाफे का एक हिस्सा वापस भी लेते हैं। यह किसी भी सफल निवेश गंतव्य की सामान्य प्रक्रिया होती है, इसलिए निवेश की वापसी इस बात का प्रमाण भी है कि भारत में निवेश लाभदायक रहा है। यदि निवेशकों को अपेक्षित प्रतिफल नहीं मिलता, तो वे नए निवेश की घोषणा नहीं करते, जबकि भारत में लगातार नई परियोजनाओं की घोषणा हो रही है।आंकड़े बोलते हैं! लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना होना स्वाभाविक है, किंतु आर्थिक बहस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। संसद में प्रस्तुत रिकॉर्ड एफडीआई, संयुक्त राष्ट्र की विश्व निवेश रिपोर्ट, वैश्विक रैंकिंग में भारत की छलांग, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में विश्व नेतृत्व और लगातार बढ़ता विदेशी विश्वास स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत आज दुनिया की सबसे आकर्षक निवेश अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। कहना यही होगा कि भारत में बढ़ता एफडीआई विकसित भारत की दिशा में बढ़ते विश्वास का सशक्त प्रमाण है। जब विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं, तब यह स्वीकार करना होगा कि अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास राजनीतिक आरोपों के सामने नहीं ठहरता, उन्हें आज केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों और भारत की बदलती आर्थिक क्षमता और स्थिर विकास यात्रा पर पूरा भरोसा है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

शिकार रोकने की आधुनिक तकनीकों से मिली 'बाघ संरक्षण' अभियानों को ऊर्जा

डॉ. रमेश ठाकुर
स्तंभकार

'अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस' मनाने का मुख्य मकसद विश्वभर में तेजी से घटती बाघों की आबादी को रोकने एवं उनके संरक्षण के प्रति समूची दुनिया को जागरूक करना है। यह दिन जंगल की शान कहे जाने वाले बाघों के लिए समर्पित है। सालाना ये दिन 29 जुलाई को पूरे संसार में मनाया जाता है। शुरुआत रूस स्थित 'पीटरर्सबर्ग टाइगर संरक्षण शिखर सम्मेलन' के दौरान वर्ष-2010 में की गई थी। विश्व में बाघों की संख्या करीब 78 फीसदी तक घट चुकी है। गनीमत है कि भारत बाघों के मामले में अभी भी टॉप पर है। वैश्विक स्तर के आंकड़ों पर गौर करें तो अनुमानित, बाघों की संख्या पूरे विश्व में लगभग 5,500 के बीच है। इनमें से 72 प्रतिशत आबादी अकेले भारत में ही है। साल 2022 बाघ गणना में भारतीय जंगलों और टाइगर रिजर्व में 3,682 जंगली बाघ थे, इनमें पिछले दो वर्षों में इजाफा ठीक-ठाक हुआ। 'ग्लोबल टाइगर दिवस-2025' की थीम थी- 'हमारे हाथों में है बाघों का संरक्षण।'

बाघों की आबादी के मामले में भारत के अलावा दूसरे पायदान पर रूस है। अखिल भारतीय बाघ जनगणना-2022 में बाघों की जितनी संख्या बताई गई थी, उनमें अब 12 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। हालांकि, संपूर्ण संख्या अगली गणना में ही सामने आएगी। बाघ संरक्षण की दिशा में बीते कुछ वर्षों से सराहनीय प्रयास हुए हैं। बाघों का सर्वेक्षण आधुनिक तकनीकों से किया जाने लगा है। प्रत्येक टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में कैमरे लगवाए गए हैं, ताकि उनकी आबादी का सही-सही आंकड़ा सामने आ सके और उनकी चहलकदमी पर नजर रखी जा सके। पिछली बाघ गणना के दौरान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एकाध बाघ दिखे तो केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को उस जगह को 58 वां टाइगर रिजर्व स्थापित कर दिया जिसका नाम 'माधव राष्ट्रीय उधान' रखा गया। यह प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है।

गौरतलब है कि भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 5 साल बाद की जाती है पिछली गणना 2022 में हुई थी, अगली गणना मार्च-2027 में करवाने का प्रस्ताव पारित है। बाघों की आबादी जितनी होनी चाहिए, उतनी है नहीं। बाघ संरक्षण पर केंद्र सरकार सालाना करीब 250 से 290 करोड़ रूपए खर्च करती है। वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर में रखे गए प्रत्येक बाघ पर साल में 20 लाख से ज्यादा खर्च होता है। आजादी से पूर्व 100 साल पहले यानी 1926 के आसपास में भारत में बाघों की आबादी सर्वाधिक एक लाख से भी अधिक हुआ करती थी, जो घटती-घटती आज कुछ हजारों तक ही सिमट गई। उत्तराखंड स्थित सिर्फ जिम कॉर्बेट में ही हजारों बाघ पाए जाते थे। हालांकि, सर्वाधिक संख्या आज भी वहीं है। पिछली गणना में 231 बाघ बताए गए थे। इस समय मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 524 बाघ हैं।

बाघों के लुप्त होते कारणों में आवासों की कमी, वन-विखंडन, अवैध शिकार, मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे मुख्य वजहें हैं। अगर ये रूक जाएं तो बाघों की संख्या एकाएक बढ़ जाएगी। एशिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां बाघ पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं उनमें, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। कुछ देश इस मामले में विलुप्ति की कगार पर हैं। बाघों का अवैध शिकार समूचे संसार में तेजी से जारी है। होता क्यों है? ये भी जानना जरूरी है।

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बाघों के अंगों की सदैव से भारी डिमांड रही है जिनमें एशियाई बाघों की सबसे ज्यादा। इसे देखते हुए बाघ संरक्षण के क्षेत्र में और सख्ती बरतने की जरूरत है। कानूनों को कठोर और जुर्माने का भारी-भरकम प्रावधान किए जाने की जरूरत है। ताकि, कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले सौ बार सोचे। पिछले एक वर्ष में विभिन्न राज्यों में करीब 75 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, कइयों को जेल भी हुई। नरसिंहपुर, बालाघाट और बांधवगढ़ में बाघों के अवैध शिकार व अंगों की तस्करी मामलों में मार्च 2025 में एक साथ दर्जनों शिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत कार्रवाही की जाती है जिसमें 3 से 7 साल की कैद का प्रावधान है। इसे रिफॉर्म किए जाने की अब जरूरत है।

जंगली बाघ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सामंजस्य को बनाए रखने में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। भारत में टाइगरों के संरक्षण के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न अभियान बीते एकाध दशकों से जारी हैं। इन अभियानों के निरंतर चलते रहने से ही भारत में इस समय 58 टाइगर रिजर्व स्थापित हैं। ये बाघ रिजर्व 19 राज्यों में फैले हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं। करीब 30 पहले भारत में बाघों की आबादी अचानक से घटनी शुरू हुई तो सरकार ने 'टाइगर टास्क फोर्स' का गठन किया। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 जुलाई 1973 को 'प्रोजेक्ट टाइगर' आरंभ करके बाघों की घटती आबादी को किसी तरह रोकना शुरू किया। इस प्रयोग से जबरदस्त फायदा हुआ।

बाघ संरक्षण निर्भर प्रजाति है। बाघों के संरक्षण में उनके रहने के निवास यानी अभयारण्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर, इन जगहों पर लगातार बढ़ती शिकारियों की गतिविधियों ने उनकी शांत जिंदगी में खलल पहुंचा दिया है। शिकारी ज्यादातर बाघ अभयारण्यों के ईद-गिर्द घात लगाए होते हैं। बाघ को देखते ही उसका शिकार कर देते हैं। कई बार खबरें ऐसी भी आई कि शिकारियों का साथ वन्य कर्मी भी देते है। ऐसे गंभीर आरोप में कर्नाटक के कई वन्य कर्मी पकड़े भी गए। इस सिंडिकेट को किसी भी तरह से रोकने की जरूरत है। अगर इन तत्वों को नहीं रोका गया तो भारत वैश्विक स्तर पर बाघ आबादी का पहला पायदान खो देगा।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अलर्ट

देर रात डिनर की आदत पड़ सकती है भारी, किडनी पर भी पड़ता है दबाव

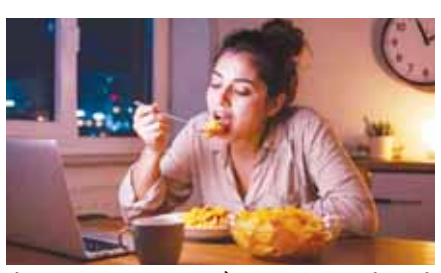

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक काम करना, मोबाइल चलाना या ओटीटी देखते हुए खाना खाना आम बात हो गई है। कई लोग रात 10-11 बजे या उससे भी देर से डिनर करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे केवल वजन बढ़ता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है। देर रात खाना खाने से शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित होती है, जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, इंसुलिन का काम, फैट स्टोरेज, नींद और लंबे समय में किडनी की सेहत पर भी असर पड़ सकता है।

एनआईएच के मुताबिक हमारे शरीर का लगभग हर अंग 24 घंटे की जैविक घड़ी के अनुसार काम करता है। सुबह और दिन के समय शरीर भोजन को बेहतर तरीके से पचाता है और ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। लेकिन रात होते-होते इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने लगती है और मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ता है। दिन की तुलना में रात में शरीर ग्लूकोज को संभालने में कम सक्षम होता है। देर रात भोजन करने से ब्लड शुगर अधिक समय तक हाई रह सकता है, जिससे समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। विशेष रूप से यदि भोजन में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और अधिक कैलोरी हो तो यह प्रभाव और बढ़ जाता है। रात में मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ने लगता है, जो नींद की तैयारी करता है। इसी दौरान इंसुलिन का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। यदि इसी समय भारी भोजन लिया जाए तो शरीर को ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लगातार ऐसा होने पर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

किडनी पर दबाव पड़ना: देर रात अधिक कैलोरी वाला भोजन करने से शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को फैट के रूप में जमा कर सकता है। समय के साथ वजन बढ़ने और पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। स्टडी से पता चलता है कि मोटापा किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे लंबे समय में किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। एनसीबीआई के अनुसार लगातार देर रात भोजन करने से ब्लड शुगर को नियंत्रण करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यदि समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़े और टाइप-2 डायबिटीज विकसित हो जाए, तो यह किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अनियंत्रित ब्लड शुगर किडनी की महीन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। देर रात खाना खाना सीधे तौर पर किडनी की बीमारी का कारण नहीं माना जाता, लेकिन यह शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित कर सकता है। इससे ब्लड शुगर नियंत्रण, इंसुलिन की कार्यक्षमता, फैट स्टोरेज और नींद पर असर पड़ सकता है। यदि यह आदत लंबे समय तक बनी रहे और मोटापा, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर विकसित हो जाए, तो किडनी की बीमारी का जोखिम भी बढ़ सकता है।

निशाना

धूप आई छप्परों में..!

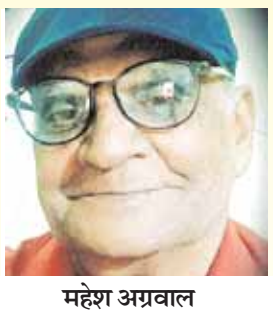

महेश अग्रवाल

धूप आई छप्परों के छेद से घर में।
यूं लगा कुछ तो उजाले हैं मुकद्दर में।
जिन्दगी अपनी खंगालो तो जरा तुम भी,
रत्न सब के सब नहीं मिलते समुंदर में।
ज़िद हवाओं की भला मैं मान लूं कैसे,
मैं चिरागों को जलाऊंगा बवंडर में।
बोल उठते हैं बहुत बेजान पत्थर भी,
डाल देते जान जब नक्काश पत्थर में।
जालिमों से डर नहीं मुंहतोड़ उत्तर दे,
धार इतनी भी नहीं होती है खंजर में।
नफरतों के चार अक्षर हार जाएंगे,
याद रख ताकत बहुत है ढाई आखर में।
हार में भी जीत हो या जीत में भी हार,
बस यही अंतर रहा पौरस - सिकंदर में।
देश अपना सोच में कुछ और आगे है,
हम समुंदर भी भरा करते हैं गागर में।
हम उड़ाते हैं कबूतर अम्न की खातिर,
चील को तो मांस दिखता है कबूतर में।

टेक्नो अपडेट

चीन ने बना ली सोलर टाइल्स, बिजली का पावर प्लांट बन जाएगी घर की छत

चीन ने ऐसे खास तरह के सोलर पैनल बनाए हैं, जो कि छतों पर टाइल्स का काम भी कर सकते हैं। इन्हें सोलर टाइल्स ही कहा जाता है। चीनी कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और डच रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी फ्लेक्सिबल सोलर फॉयल के जरिए इस दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। इस तकनीक की मदद से टाइलें छत को सुंदर बनाने के साथ-साथ खुद ही बिजली बनाने वाले पावर प्लांट के तौर पर काम भी करेगी। चीन की दिग्गज कंपनियां सोलर टेक्नोलॉजी को बिल्कुल नया आकार दे रही हैं। इन्होंने सोलर पैनलों को टाइल के आकार में ढाला है। इसकी वजह से यह सामान्य सोलर पैनल की तुलना में काफी हल्की, सुंदर और फ्लेक्सिबल होती हैं। इसकी वजह से इन्हें घुमावदार छतों पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। इनकी खास बात है कि इनमें Perovskite सोलर सेल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि कम लागत में ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं।

इस तकनीक की मदद से चीन अपने शहरों को खुद बिजली बनाने के काबिल बना रहा है। इन टाइल्स की खूबी है कि यह घर की छत का हिस्सा बन जाते हैं और घर की छत अपने आप में बिजली बनाने वाली यूनिट बन जाती है। इसके अलावा इसमें पेरोव्स्कैट सेल का इस्तेमाल होता है, जो कि सूरज की रोशनी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है और कम रोशनी में भी खूब बिजली बनाता है। इस तकनीक की वजह से अलग से सोलर पैनल के रख-रखाव की टेंशन खत्म हो जाती है।टाइल्स हल्की और मुड़ने लायक होती हैं, जिससे इन्हें समतल ही नहीं बल्कि घुमावदार छतों पर भी आसानी से लगाया जा सकता है। टाइल्स से उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा को सीधे घर के इलेक्ट्रिकल ग्रिड या इनवर्टर से जोड़ दिया जाता है, जिससे बाहरी बिजली पर निर्भरता तुरंत कम हो जाती है।?

भविष्य में इस तकनीक को जब बड़े स्तर पर अपनाया जाएगा तो घर सिर्फ बिजली की खपत ही नहीं करेंगे, बल्कि बिजली खुद पैदा भी करेंगे। यही वजह है कि घनी आबादी वाले शहरी इलाकों के लिए यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है।

पेरोव्स्कैट तकनीक के कारण सोलर टाइल्स की दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है और इनकी उम्र व मजबूती को बढ़ाया जा रहा है।

यूजर्स गाइड

मिलेगा पुराने पीएफ खाते में पड़ा पैसा, नई वेबसाइट से घर बैठे करें क्लेम और ट्रांसफर

नौकरी बदलने के बाद पुराने PF खाते को भूल जाना एक आम समस्या रही है लेकिन सरकार इसे दूर करने के लिए नया डिजिटल पोर्टल तैयार किया है। इसकी मदद से ईपीएफ सदस्य अपने पुराने और निष्क्रिय पड़े पीएफ खातों का पता लगा सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और आसानी से अपने एक्टिव UAN अकाउंट मे ट्रांसफर कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पोर्टल या वेबसाइट का नाम E-PRAAPTI है।

यह आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए पुराने पीएफ खातों में मौजूद राशि को पाने में मदद करेगा। इस पोर्टल की जानकारी लोकसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO ने पुराने खातों को वापस पाने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए यह खास पोर्टल बनाया है। यह नया ई-पोर्टल सदस्य की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन का उपयोग करता है। पहचान वेरिफाई होने के बाद इस नए पोर्ट्ल की मदद से लोग अपने निष्क्रिय खातों को ट्रैक करने के साथ-साथ वहीं से अपनी पुरानी पीएफ राशि को सुरक्षित रूप से अपने मौजूदा यूएएन में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा इस पोर्टल पर आप पुरानी पीएफ राशि को क्लेम भी कर सकेंगे। यहां गौर करने वाली बात है कि यह पोर्टल उन लोगों की मदद कर पाएगा जिन्हें अपने पुराने खाते की सही जानकारी है। पोर्टल का दायरा उन लोगों के लिए अभी नहीं बढ़ रहा है जिन्हें अपना पुराना पीएफ नंबर या आइडेंटिफिकेशन याद नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार नए सिस्टम से कागजी कार्रवाई कम होगी और बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के लोगों का काम हो पाएगा। इसके अलावा, वेरिफिकेशन के लिए KYC अपडेट के लिए संयुक्त घोषणा पत्र भी डिजिटल रूप से जमा किया जा सकेगा। इन सुविधाओं की वजह से पुराने निष्क्रिय ईपीएफ खातों का निपटान बेहद तेज, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के हो सकेगा। इसके साथ ही बार-बार नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को अब दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी। अक्सर देखा गया है कि नौकरियां बदलने पर या ह्र सिस्टम लागू होने से पहले के पुराने खातों की जानकारी कर्मचारी भूल जाते हैं।

न्यूज विंडो

गुरु पूर्णिमा पर गंज हनुमान मंदिर में विशाल भंडारा एवं गुरु पूजन

गंजबासौदा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव शहर सहित पूरे ग्रामीण अंचल में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों एवं आश्रमों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुजनों का पूजन-अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व को स्मरण किया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंज हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और प्रसादी ग्रहण कर धर्मलाभ अर्जित किया। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर मंदिर के पूज्य महंत महेश्वर दास त्यागी जी महाराज के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भक्तों ने पुष्पमालाएं अर्पित कर उनका सम्मान किया तथा गुरु चरणों में नमन करते हुए जीवन में सदैव धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महंत श्री ने श्रद्धालुओं को गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि गुरु ही मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाता है। भंडारे के सफल आयोजन में मंदिर समिति, सेवादारों एवं स्थानीय श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसादी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की गईं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मंदिर परिसर देर शाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही और पूरा वातावरण भक्ति, सेवा एवं श्रद्धा से सराबोर रहा।

निजी कंपनियों में प्राइवेट नंबर वाहनों से सरकार को राजस्व का नुकसान

शहडोल। संभाग में संचालित कई निजी कंपनियों में किराये के कार्य के लिए निजी (प्राइवेट) पंजीकरण वाले चार पहिया वाहन, जैसे कार, बोलेरो एवं अन्य हल्के वाहन लगाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि व्यावसायिक उपयोग के लिए निजी पंजीकरण वाले वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, तो इससे शासन को वाणिज्यिक वाहन कर एवं अन्य राजस्व का नुकसान हो सकता है। साथ ही, यह मोटर वाहन नियमों के अनुपालन से जुड़ा गंभीर विषय भी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि ऐसे किसी वाहन से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है और वाहन का उपयोग उसकी पंजीकरण श्रेणी या बीमा शर्तों के विपरीत पाया जाता है, तो बीमा दावा (क्लेम) प्रभावित हो सकता है। इससे वाहन मालिक, कंपनी और दुर्घटना पीड़ितों को कानूनी व वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जनहित में आवश्यक है कि परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं जिला पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से शहडोल संभाग की सभी निजी कंपनियों में संचालित किराये के वाहनों की जांच करें। यदि किसी कंपनी में व्यावसायिक कार्य के लिए निजी पंजीकरण वाले वाहन संचालित पाए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा केवल वैध वाणिज्यिक (कमर्शियल) परमिट एवं आवश्यक दस्तावेज वाले वाहनों का ही उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। इससे शासन के राजस्व की सुरक्षा होगी, सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और भविष्य में किसी दुर्घटना की स्थिति में कानूनी जटिलताओं से भी बचा जा सकेगा।

गिरधर समूह संस्थान एवं गिरधर पब्लिक स्कूल में मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव

मंडीदीप। गिरधर समूह संस्थान एवं गिरधर पब्लिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, सम्मान एवं उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों का तिलक, पुष्प एवं सम्मान-पत्र भेंट कर सम्मान किया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु-शिष्य परंपरा का महत्व प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान के सचिव अरविंद पाटीदार ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति के महान ऋषि एवं महाभारत जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य के रचयिता हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जीवन में गुरुजनों के मार्गदर्शन का सम्मान करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष रघुनाथ पाटीदार, सचिव अरविंद पाटीदार, प्रबंध संचालक नीलेश पाण्डेय, प्राचार्य अनुराग जीवन मसीह, रामशंकर ठाकुर, लोकेश पाल एवं सांस्कृतिक प्रमुख श्रीमती शिल्पी जैन सहित संस्थान के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन गुरु वंदना एवं सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए किया गया।

बरही के पुराने बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टला, नगर की यातायात व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

ब्रेक फेल होने से कटनी में बेकाबू बस दुकान में घुसी, दो बाइक चकनाचूर, दो लोग घायल

कटनी दोपहर मेट्रो

जिले के बरही नगर में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां गहरवार सर्विस की बस का ब्रेक फेल होने से बेकाबू बस पुराने बस स्टैंड स्थित डोली रोड पर एक दुकान में जा घुसी। हादसे में दुकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सड़क किनारे खड़ी दो बाइक बस की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में दुकान की ओर बढ़ी। इस दौरान सड़क किनारे खड़े खेमराज सोनी और शंकर गुप्ता बस की चपेट में आकर उसके नीचे दब गए। घटना होते ही स्थानीय नागरिकों ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया। लोगों ने बस के नीचे फंसे दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। समय रहते लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा जनहानि और अधिक हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने और यातायात बहाल करने की कार्रवाई शुरू की गई। हादसे के बाद कुछ देर तक पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहा। इस दुर्घटना के बाद बरही नगर में वर्षों से लंबित बाईपास निर्माण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर के बीच से भारी वाहनों और यात्री बसों का लगातार आवागमन होता है, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से बाईपास निर्माण की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। नागरिकों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण नगरवासी लगातार जोखिम उठाने को मजबूर हैं। पूर्व में भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान गई और कई घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।

बिगड़ी व्यवस्था से लोगों में नाराजगी

स्थानीय लोगों ने नगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सड़क किनारे बढ़ते अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग और संकरी सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है। नगर परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने से समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। हादसे के बाद नागरिकों ने प्रशासन से बरही बाईपास निर्माण को प्राथमिकता देने, सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाने, भारी वाहनों के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने तथा नगर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं।

पटवारी ने एसडीएम कार्यालय में खाया जहर वेतन न मिलने और जांच के दबाव से था आहत

शिवपुरी। दोपहर मेट्रो

जिले के कोलारस में एसडीएम कार्यालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब रन्नौद तहसील में पदस्थ एक पटवारी ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। घटना के बाद कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तत्काल उसे कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है।

अस्पताल में भर्ती पटवारी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके अनुसार रन्नौद में एक नामांतरण प्रकरण में उनसे तकनीकी त्रुटि हो गई थी। गलती स्वीकार करते हुए उन्होंने पहले भी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर माफी मांगी थी और परिवार सहित क्षमा याचना की थी। प्रदीप का आरोप है कि इसके बाद से उनका वेतन रोक दिया गया। पिछले आठ-नौ महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली, जिससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को अन्य पटवारियों का वेतन जारी हो गया, लेकिन उनका वेतन नहीं आया। इसी से आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया। कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने पटवारी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित कर्मचारी पर जमीनों के नामांतरण में नियमों की अनदेखी के आरोप हैं और इस मामले में विभागीय जांच चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटवारियों का वेतन एसडीएम कार्यालय से जारी नहीं होता, बल्कि तहसील कार्यालय के माध्यम से भुगतान होता है। उनके अनुसार संबंधित पटवारी पिछले कई महीनों से तहसील में उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे में अनुपस्थिति के कारण उनका वेतन लंबित हो सकता है। एसडीएम ने यह भी कहा कि विभागीय जांच और संभावित कार्रवाई के दबाव में आकर पटवारी ने यह कदम उठाया होगा।

जानकारी के मुताबिक प्रदीप गुप्ता अपने कुछ परिजनों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बैग से एक शीशी निकाली और उसमें मौजूद जहरीला पदार्थ पी लिया। घटना के बाद कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें संभाला और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही कोलारस थाना पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

चोर पकड़ने पहुंची यूपी-एमपी पुलिस पर टूट पड़े गांव वाले, दो आरक्षक हुए जख्मी

राजगढ़। दोपहर मेट्रो

राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र में उस समय तनाव फैल गया जब चोरी के एक मामले में आरोपी को पकड़ने पहुंची संयुक्त पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में बोड़ा थाने के दो आरक्षक घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के महरौनी थाने में दर्ज एक चोरी के प्रकरण में कुछ आरोपियों के राजगढ़ जिले के कड़िया सांसी गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना पर यूपी पुलिस महरौनी थाने की टीम स्थानीय बोड़ा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के लिए गांव पहुंची। पुलिस टीम जब बताए गए घर पर दबिश देने पहुंची तो वहां मौजूद परिजनों और अन्य लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले में बोड़ा थाने में पदस्थ दो आरक्षक चोटिल हो गए। हमले में घायल हुए दोनों आरक्षकों को तुरंत बोड़ा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बोड़ा थाना प्रभारी अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू किया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। इस मामले में बोड़ा पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने, बलवा और अन्य धाराओं के तहत 6 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि हमले के दौरान आरोपी और उनके परिजन मौके से फरार हो गए। पुलिस अब फरार लोगों के ठिकानों पर दबिश दे रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बोड़ा पुलिस के अनुसार यूपी के महरौनी थाने में हुई चोरी की वारदात के तार कड़िया सांसी गांव से जुड़े थे। इसी आधार पर वहां रहने वाले संदिग्धों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने स्थानीय पुलिस से मदद मांगी थी।

स्वास्थ्य केंद्र से निकली महिला, इमली के पेड़ के नीचे बनी मां, टीकमगढ़ में लापरवाही का नतीजा

टीकमगढ़। दोपहर मेट्रो

एक ओर जहां सरकार मातृ एवं शिशु मृत्युदर कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में इसी से जुड़ी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की ही नहीं, बल्कि प्रसूता के परिजन की भी गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। वो तो गनीमत रही कि, महिला का सड़क किनारे सुरक्षित प्रसव हो गया और स्वास्थ्य अमला भी मौके पर पहुंच गया, वरना इस तरह के मामले में किसी बड़ी अनहोनी को नकारा नहीं जा सकता।

दरअसल ग्राम ककारवाहा में रहने वाली गीता कुशवाहा को प्रसव वेदना होने पर परिजन उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव धसान लेकर पहुंचे थे। यहां पर डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे खून की कमी बताई। यहां पर महिला को 6.7 हीमोग्लोबिन निकला था। प्रसव के समय खून की और कमी होने पर सुरक्षा को लेकर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया और परिजन को समझा भी दिया। इसके बाद परिजन जिला अस्पताल नहीं गए। वहीं, सुबह सूचना मिली कि गीता ने स्वास्थ्य केंद्र से करीब एक किलोमीटर दूर सड़क किनारे इमली के पेड़ के नीचे बच्ची को जन्म दिया है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और प्रसव प्रक्रिया पूरी कराई। इसके बाद जच्चा - बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। इस मामले में परिजन ने उपचार न करने के आरोप लगाए हैं। गीता के पति जसरथ ने बताया कि वो अपनी पत्नी को भर्ती कराकर बुआ को लेने चला गया था। बुआ को छोड़ने के बाद वो मां को लेने गया और लौटकर आया तो डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए भेज दिया। यहां पर उसका उपचार ही नहीं किया गया है। वहीं, अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, महिला में खून की कमी होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था।

सरकारी जमीन पर कब्जे का बड़ा खुलासा

अपर कलेक्टर के रीडर के नाम दर्ज भूमि निरस्त

टीकमगढ़। दोपहर मेट्रो

जिले में सरकारी जमीनों पर फर्जी तरीके से नामांतरण कर कब्जा करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने जांच के बाद सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर के रीडर शंकर प्रसाद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, मां और पुत्र के नाम दर्ज 3.5 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि का नामांतरण निरस्त कर उसे पुनः शासकीय अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

जांच में सामने आया कि शंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने अपने पद और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न सरकारी जमीनों को फर्जी दस्तावेजों और नियमों की अनदेखी कर अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज करा लिया था। इनमें ग्राम उत्तरी करीं और मोगनगढ़ क्षेत्र की कई शासकीय भूमि शामिल हैं। बताया गया कि कुछ जमीनें वर्ष 1969-70 से शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज थीं, लेकिन बाद में फर्जी आदेशों और नामांतरण के जरिए निजी नामों पर दर्ज करा ली गईं।

आदेशों को भी अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया गया

कलेक्टर के आदेश में उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किए गए थे। वहीं कई मामलों में भूमि के बदले दूसरी भूमि की अदला-बदली भी नियमों के विपरीत कर दी गई थी। जांच में पाया गया कि लगभग 1.126 हेक्टेयर भूमि पहले श्रीवास्तव की मां के नाम दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर दूसरी शासकीय भूमि उनके पुत्र राहुल श्रीवास्तव के नाम दर्ज करा ली गई। बाद में इन आदेशों को भी अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया गया।

आरोप-सरकारी जमीनों पर कब्जा

मामले की जांच शिकायत मिलने के बाद शुरू हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरकारी कर्मचारी रहते हुए शंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने प्रभाव का दुरुपयोग कर कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया। जांच के दौरान दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्रशासन ने पाया कि नामांतरण की पूरी प्रक्रिया नियमों के विपरीत थी।

प्रशासनिक व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने सभी विवादित आदेश निरस्त करते हुए संबंधित जमीनों को पुनः सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद जिले में सरकारी भूमि पर हुए कथित फर्जी नामांतरण और कब्जों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि इस प्रकरण के बाद ऐसे अन्य मामलों की भी जांच तेज हो सकती है।

मेट्रो एंकर गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम में कोचिंगबाज सरकारी शिक्षकों को लेकर राज्यमंत्री बोले-

'दो दिन में कार्रवाई करो, वरना मैं करूंगा'

राजगढ़। दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में गुरु पूर्णिमा के दिन सभी स्कूलों सहित अन्य शिक्षा संस्थानों में कार्यक्रम हुए। ब्यावरा में सांदीपनि विद्यालय में आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान मंच से राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार ने चेतावनी दे डाली। उन्होंने सीईओ-डीईओ को चेताया कि दो दिन में कोचिंग बाज सरकारी शिक्षकों पर कार्रवाई करो, वरना मैं करूंगा।

मंत्री ने निजी कोचिंग चलाने और बच्चों को वहां आने के लिए मजबूर करने वाले सरकारी शिक्षकों पर जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए मंच पर मौजूद जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले और जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) श्रवण पाटीदार को ऐसे शिक्षकों पर दो दिन के भीतर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री पंवार ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि विभाग ने कार्रवाई नहीं की, तो वे खुद मैदान में उतरकर सख्त कदम उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि मीडिया ने पीएमश्री व सांदीपनि स्कूलों के शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग में पढ़ाने और छात्रों पर दबाव बनाने के मामले को प्रमुखता से उजागर किया था। जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के बाद अब मंत्री की सीधी सख्ती से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब सभी की नजरें अगले दो दिनों में होने वाली विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं। शिक्षा व्यवस्था पर तल्ख लहजे में बोलते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी जानकारी है कि नगर में कौन-कौन से सरकारी शिक्षक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों पर कोचिंग का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर सीएम राइज और सांदीपनि स्कूल इसलिए बनाए हैं, ताकि बच्चों को निजी स्कूलों और कोचिंग पर निर्भर न रहना पड़े। यदि सरकारी शिक्षक ही विद्यार्थियों को कोचिंग की तरफ धकेलेंगे, तो इन आधुनिक स्कूलों को बनाने का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। सरकारी सेवा में रहते हुए निजी लाभ के लिए छात्रों का इस्तेमाल किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का इंतजार किए बिना खुद निगरानी करें।

गुरुजनों का सम्मान, विद्यार्थियों संग फर्श पर बैठकर संवाद

महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व-2026 के इस कार्यक्रम में मंत्री पंवार ने गुरुजनों का सम्मान किया और विद्यार्थियों के बीच जाकर बैठकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रेरणास्रोत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशाला और खेल सुविधाओं के माध्यम से शिक्षा में व्यापक बदलाव ला रही है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश गुर्जर और जिला पंचायत सीईओ ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान परिसर में पौधारोपण भी किया गया। आयोजन में जनप्रतिनिधि, डीईओ, प्राचार्य एसएन यादव और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

न्यूज विंडो

शासकीय महाविद्यालय में सांदीपनी गुरु पर्व श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न

तेंदूखेड़ा। शासकीय महाविद्यालय तेंदूखेड़ा में सांदीपनी गुरु पर्व का आयोजन श्रद्धा, सम्मान एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के पूजन-अर्चन एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक सुखदेव साहू का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य शंकर सिंह ठाकुर ने भारतीय संस्कृति में गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन को सही दिशा, संस्कार और व्यक्तित्व निर्माण का आधार भी प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने गुरुजनों का सदैव सम्मान करने तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। छात्र हर्ष यादव ने गुरु महिमा पर आधारित भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित जनों ने सराहा। वहीं छात्राओं के लिए गुरु महिमा विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने गुरु के महत्व पर प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान बी.ए. प्रथम वर्ष की छात्राओं ने माँ सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता रही। जिससे आयोजन सफल एवं प्रेरणादायी बना। महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक स्टाफ ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

ग्राम रामादेही में जला ट्रांसफार्मर ग्रामीणों ने शीघ्र बदलने की मांग की

तेन्दूखेड़ा। ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम रामादेही के ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से गांव का जला हुआ ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार गांव का विद्युत ट्रांसफार्मर लगभग एक माह पूर्व जल गया था, लेकिन अब तक नया ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार मौखिक रूप से विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत एवं अनुरोध किया गया, किंतु समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि वे नियमित रूप से घरेलू एवं कृषि पंपों के बिजली बिल जमा करते हैं, इसके बावजूद उन्हें मूलभूत विद्युत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। वर्तमान वर्षा ऋतु में पेयजल संकट गहरा गया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तथा रात्रि के समय अंधेरे के कारण जहरीले जीव-जंतुओं, मच्छरों और उमस से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्त ग्रामवासियों ने कनिष्ठ अभियंता, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तेन्दूखेड़ा से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्राम रामादेही का जला हुआ ट्रांसफार्मर अतिशीघ्र बदलवाकर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके।

तेज बारिश से कुदपुरा-सर्रा मार्ग की पुलिया क्षतिग्रस्त, आवागमन प्रभावित

तेंदूखेड़ा। नगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित कुदपुरा-सर्रा मार्ग पर स्थित पुलिया क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से दोपहिया, चारपहिया एवं भारी वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने समय रहते सड़क एवं पुल-पुलियों का रखरखाव नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। लगातार हुई बारिश के कारण पुलिया के दोनों ओर सड़क का डामरीकरण भी बह गया है, जिससे मार्ग पर आवागमन और अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय-समय पर सड़क और पुल-पुलियों की मरम्मत एवं रखरखाव किया जाता, तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी मार्ग की उक्त पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उस समय लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्य कराकर पुलिया को पुनः यातायात योग्य बनाया गया था, लेकिन इस बार हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर पुलिया को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इससे क्षेत्र के ग्रामीणों सहित इस मार्ग से प्रतिदिन आवागमन करने वाले लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग की एसडीओ मनीषा मोगनिया से चर्चा किए जाने पर उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल-पुलियों के सुधार कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वर्क ऑर्डर जारी होते ही लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी क्षतिग्रस्त मार्गों और पुल-पुलियों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जाएगी।

बारिश से चौपट हुई थी खरीफ की फसल, जल्द बीमा राशि दिलाने की मांग

सर्वे में नुकसान की पुष्टि के बावजूद किसानों को नहीं मिली बीमा राशि

बीना। दोपहर मेट्रो

फसल बीमा योजना के तहत हर साल क्षेत्र के किसान एक करोड़ रुपए से अधिक का प्रीमियम जमा कर रहे हैं, लेकिन नुकसान होने के बाद भी उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले वर्ष खरीफ सीजन में लगातार हुई बारिश के कारण सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बाद भी क्षेत्र के किसानों को एक रुपए बीमा राशि भी नहीं आई है।

पिछले वर्ष खरीफ सीजन में बारिश ज्यादा और नदी किनारे स्थित खेतों में बाढ़ आने से फसलें बर्बाद हो गई थीं। सबसे ज्यादा बोवनी सोयाबीन की हुई थी और बारिश के कारण इसका उत्पादन 1 से 2 क्विंटल एकड़ निकला था। आर्थिक नुकसान झेलने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन अन्य जिलों और तहसीलों में बीमा राशि आने के बाद भी क्षेत्र के किसानों को कुछ नहीं मिला, जिससे उनका आक्रोश बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि हर वर्ष समय पर फसल बीमा के लिए प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन जब नुकसान की भरपाई की बारी आती है, तो उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता

है। उनका आरोप है कि सर्वे में नुकसान की पुष्टि होने के बाद भी बीमा राशि नहीं मिली है। किसानों ने शीघ्र बीमा राशि जारी करने की मांग की है। बीना के साथ-साथ मालथौन, खुरई, राहतगढ़ तहसील के किसान भी बीमा राशि का इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष भी खरीफ फसल के लिए फसल बीमा के लिए प्रीमियम काटा जाने लगा है। कई किसानों ने प्रीमियम जमा करना भी बंद कर दिया है।

सर्वे के अनुसार भेजी थी रिपोर्ट

एआईसी बीमा कंपनी के डीआर सौरभ जैन ने बताया कि राजस्व, कृषि विभाग द्वारा जो सर्वे कराया गया था, उसके अनुसार नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। बीमा क्लेम क्यों नहीं मिला है इसकी जानकारी नहीं है। बीना सहित मालथौन, खुरई, राहतगढ़ तहसील में भी बीमा राशि नहीं आई है।

किया जा रहा है कैलकुलेशन

कृषि उप संचालक राजेश त्रिपाठी ने बताया कि बीमा राशि न आने पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है। वर्तमान में फसल बीमा राशि का कैलकुलेशन किया जा रहा है और जल्द ही बीमा राशि किसानों के खातों में आ जाएगी।

गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा का संगम

हनुमान मंदिर के पुजारी मुकेश शास्त्री का भक्तों ने किया सम्मान

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जरजोला रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में श्रद्धा, आस्था और सम्मान का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। मंदिर के पुजारी एवं विद्वान आचार्य शास्त्री मुकेश पचौरी का भक्तों ने पुष्पमालाएं पहनाकर, श्रीफल एवं शॉल भेंट कर सम्मान किया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने कहा कि गुरु केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाली वह शक्ति है जो अपने शिष्यों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गुरु के मार्गदर्शन से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। कार्यक्रम में भक्तों ने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु के आशीर्वाद और शिक्षा से ही जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मविश्वास का संचार होता है। गुरु पूर्णिमा पर शास्त्री मुकेश पचौरी का सम्मान कर भक्तों ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। मंदिर परिसर में पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने हनुमानजी के दर्शन-पूजन के साथ गुरु वंदना की और समाज में गुरु परंपरा को सुदृढ़ बनाए रखने का संदेश दिया।

सोनमुड़ा में टूटी रैलिंग, उखड़ी टाइल्स और जर्जर सुविधाओं से बढ़ा हादसे का खतरा

अमरकंटक। दोपहर मेट्रो

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक नगरी अमरकंटक का प्रमुख पर्यटन स्थल सोनमुड़ा इन दिनों बदहाल व्यवस्थाओं के कारण चर्चा में है। करोड़ों रुपये की लागत से प्रसाद योजना के तहत विकसित किए गए इस स्थल पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर लगी लोहे की सुरक्षा रेलिंग कई स्थानों पर टूटकर जमीन पर पड़ी है, जबकि कई हिस्सों में रेलिंग पूरी तरह गायब हो चुकी है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सोनमुड़ा में वर्षभर प्रदेश और देशभर से लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचते हैं। वर्तमान स्थिति में सीढ़ियों के किनारों पर रेलिंग न होने से जरा-सी असावधानी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वहीं कई स्थानों पर सीढ़ियों की टाइल्स उखड़कर बिखर चुकी हैं, जिससे पैदल चलने वालों के फिसलने और चोटिल होने की आशंका बनी रहती है। इतना ही नहीं, लाखों रुपये की लागत से बनाई गई

कैंटीलीवर (दर्शक मंच) के समीप स्टील की सुरक्षा ग्रिल भी कई जगह उखड़ चुकी है और धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ रखरखाव व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोनमुड़ा के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से लगाए गए नाइट लाइट के खंभे भी कई स्थानों पर उखड़कर इधर-उधर पड़े हैं। लंबे समय से इनकी मरम्मत नहीं होने के कारण पूरा परिसर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण खोता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन स्थल पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन रखरखाव के अभाव में सुविधाएं तेजी से जर्जर होती जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने मांग की है कि जिला प्रशासन एवं संबंधित विभाग तत्काल स्थल का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त रेलिंग, उखड़ी टाइल्स, टूटी सुरक्षा ग्रिल और खराब प्रकाश व्यवस्था की मरम्मत कराए। साथ ही प्रसाद योजना के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराकर यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।

रीवा में चने के ठेले पर विवाद पड़ा भारी

पिता के रिटायरमेंट से दो दिन पहले कांग्रेस नेता के बेटे की छिन गई सांसें

रीवा। दोपहर मेट्रो

प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस दतिया विधानसभा सीट के उप चुनाव में प्रचार में लगी थी वहीं, दूसरी तरफ रीवा में जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर पदस्त कांग्रेस नेता की हत्या ने हड़कंप मचा दिया। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ते-बढ़ते हिंसक हो गया। तीन लोगों ने मिलकर कांग्रेस नेता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुट गए है। कांग्रेस कार्यकर्ता आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दरअसल रीवा शहर में सरेराह बदमाशों ने आदिवासी कांग्रेस की युवा इकाई के जिला अध्यक्ष अमित कोल की ताबड़तोड़ चाकू से वार कर हत्या कर दी। खून से लथपथ पड़े अमित को लोगों की मदद से अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार, शांति विहार कॉलोनी निवासी अमित कोल के पिता सुदर्शन (30) मंगलवार रात पड़रा स्थित कल्याण पेट्रोल पंप केसामने बंद सांची पार्लर के पास खड़े थे। इस दौरान कुछ युवकों से उनका विवाद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, चने के ठेले पर अनिल का युवकों से मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया था।

विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने अमित पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़ा। बेखौफ आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे तो युवक जख्मी पड़ा था। उसको संजय गांधी अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत्यु घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक के पेट में गंभीर चोट आई थी।

छेड़छाड़ व मारपीट मामले में कार्रवाई

दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज आरोपियों का निकाला जुलूस

धार। दोपहर मेट्रो

शहर के घोड़ा चौपाटी क्षेत्र में 28 जुलाई की शाम हुई हिंसक मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। वहीं, क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और खौफ खत्म करने के उद्देश्य से पुलिस ने आरोपियों का घटनास्थल पर जुलूस भी निकाला।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत शहर के लालबाग क्षेत्र से हुई थी, जहां एक युवती का पीछा करने और छेड़छाड़ को लेकर दीपक जायसवाल (निवासी ओंकारनगर) और अजय यादव उर्फ श्याम दुबेला (निवासी कुम्हारगड्डा) के बीच कहासुनी हुई थी। इसी बात को लेकर 28 जुलाई की शाम लगभग 7:00 बजे घोड़ा चौपाटी पर दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट के दौरान दीपक जायसवाल और उसके साथी कुलदीप बौरासी तथा अजय यादव व उसके भाई सोमेश के बीच तीखी हाथापाई हुई। इस दौरान लोहे के पलटे से किए गए वार से सोमेश के सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक धाराएं भी लगाई गई हैं। विवेचना के दौरान पुलिस टीम आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची, जहां बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों का चौराहे से जुलूस निकाला। मामले में आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुए घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का पलटा भी जब्त कर लिया गया है। मामले को लेकर कोतवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या अपुष्ट खबरें प्रसारित न करें। पुलिस द्वारा मामले की निष्पक्ष विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मेट्रो एंकर | वीमेन प्रीमियर लीग सीजन-1 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन

महिलाओं ने थामा बल्ला, जीता सभी का दिल

नरसिंहपुर। दोपहर मेट्रो

नमामि वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय चाणक्य स्कूल टर्फ केज में 19 से 26 जुलाई तक आयोजित वीमेन प्रीमियर लीग सीजन-1 नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। 19 जुलाई को मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी संध्या कोठारी, माया राजपूत, निशा सोनी एवं राजेन्द्र राजपूत के आतिथ्य में शुरू हुए इस 5-ओवर और 7-खिलाड़ियों वाले अनोखे मानसून स्पेशल फॉर्मेट में जिले की 12 टीमों ने हिस्सा लिया।

इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात नगर की प्रतिष्ठित संस्था काया इंटरनेशनल योग स्टूडियो का क्रिकेट के क्षेत्र में ऐतिहासिक पर्दापण (डेब्यू) रहा। काया ने प्रतियोगिता में अपनी दो टीमों। काया सीनियर सुपर वीमेन और काया जूनियर सुपर स्टार्स को मैदान में उतारा। जहां काया सीनियर

सुपर वीमेन टीम में श्रीमती सुमन शर्मा (कप्तान), भारती रघुवंशी (उप-कप्तान), सिंधु नेमा, शोभना गुप्ता, मालती विश्वकर्मा, अनुराधा कोठारी शामिल थी। वहीं काया जूनियर सुपर स्टार्स टीम में सुश्री इंदु सिंह (कप्तान), रानू श्रीवास्तव (उप-कप्तान), सीमा नामदेव, गुंजेश्वरी लखेरा, मीना शर्मा, सुश्री देवांशी लखेरा, सुश्री आस्था लखेरा एवं सुश्री अदिति नेमा का सहभागिता रही। इन दोनों टीमों की खास बात यह रही कि एक-दो खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी महिलाओं ने जीवन में पहली बार हाथ में बल्ला थामा था। 18 से लेकर 65 वर्ष तक की आयु की इन वीरांगनाओं ने मैदान पर उतरकर यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और जज्बा हो तो कोई भी मैदान फतह किया जा सकता है।

काया जूनियर टीम की उप-कप्तान श्रीमती रानू श्रीवास्तव ने अपने ऑलराउंड और शानदार प्रदर्शन के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, 65 वर्ष की उम्र में जहां सामान्यतः लोग आराम को तरजीह देते हैं, उस उम्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरकर काया सीनियर टीम की कप्तानी करने और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए श्रीमती सुमन शर्मा को विशेष स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।।दोनों ही टीमों ने दो-दो लीग मैच खेले और विरोधी टीमों को बराबरी की टक्कर दी। नए होने के बावजूद काया की खिलाड़ियों ने एक-दो गेंदों में आउट होने के बजाय क्रीज पर टिककर सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया और प्रतिद्वंद्वी टीमों के सामने एक मजबूत लक्ष्य रखा। काया इंटरनेशनल योग स्टूडियो की इस अनूठी पहल और खिलाड़ियों के जीवट खेल प्रदर्शन की पूरे नगर और आयोजन समिति द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है।

ग्लासगो में भारत का दमदार प्रदर्शन, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में बढ़ा मेडल का भरोसा

श्रीशंकर का दूसरा रजत, पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड-सिल्वर की ऐतिहासिक वन-टू फिनिश

नई दिल्ली, एजेंसी

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ी इतिहास रच रहे हैं। एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां अपने नाम कीं। स्टार लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया। वहीं पैरा एथलेटिक्स की पुरुष 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पदक जीतकर पहली बार वन-टू फिनिश हासिल की। दूसरी ओर मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कम से कम 10 पदक पक्के कर लिए।

27 वर्षीय मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप स्पर्धा में 8.09 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन्ग जंप में लगातार दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इससे पहले उन्होंने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भी रजत पदक जीता था।

इस मुकाबले में जमैका के ताजे गेल ने 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि स्कॉटलैंड के स्टीफन मैकेंजी 8.08 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। भारत के एक अन्य खिलाड़ी लोकेश सत्यनाथन 7.97 मीटर की छलांग के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

पैरा एथलेटिक्स में भारत की ऐतिहासिक वन-टू फिनिश

एथलेटिक्स के बाद पैरा एथलेटिक्स में भी भारत ने इतिहास रच दिया। पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का नया गेम रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता। उनके पीछे भारत के ही मोहम्मद बासिल मोरसिंगानकथ ने 10.83 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक रहा। इससे पहले मीराबाई चानू और शर्मिला ढाका देश को गोल्ड दिला चुकी थीं। इन सफलताओं के बाद भारत के खाते में अब कुल 15 पदक (3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज) हो चुके हैं और भारतीय दल पदक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गया है।

मुक्केबाजों ने पक्के किए कम से कम 10 पदक

भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन भी जारी है। बुधवार को कई भारतीय बॉक्सरों ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिसके साथ भारत के कम से कम 10 पदक तय हो गए हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने वालों में साक्षी चौधरी (51 किग्रा), अरुंधति चौधरी (70 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), अंकुश पंघाल (80 किग्रा), नरेंद्र बरवाल (+90 किग्रा) और विश्व चैंपियन जैस्मिन लाम्बोरिया (57 किग्रा) शामिल हैं। इससे पहले लवलीना बोरगोहेन, प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादुमणि सिंह भी अंतिम चार में जगह बना चुके थे। दिन के अंतिम मुकाबले में जैस्मिन लाम्बोरिया ने इंग्लैंड की एलिस ग्लिन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। इस प्रदर्शन के साथ भारत ने बर्मिंघम 2022 में मुक्केबाजी में जीते सात पदकों के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

एथलेटिक्स में खिलाड़ियों ने बनाई फाइनल में जगह

भारत के यशस पालाक्ष और संथोष के तमिलारासन ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में प्रवेश किया। दोनों खिलाड़ी अपनी-अपनी हीट में तीसरे स्थान पर रहे और सर्वश्रेष्ठ समय वाले हारने वाले खिलाड़ियों के रूप में फाइनल में पहुंचे। महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में मनप्रीत सिंह 17.49 मीटर के प्रयास के साथ चौथे स्थान पर रहीं और पदक से मामूली अंतर से चूक गईं। वहीं राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तजिंदरपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉट पुट के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। तूर ने 20.14 मीटर और गिल ने 19.95 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। इसके अलावा नेशनल रिकॉर्डधारी अनिमेष कुजूर ने 200 मीटर स्पर्धा में 20.46 सेकंड का सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई।

2027 वर्ल्ड कप को लेकर कैफ की बड़ी सलाह

रोहित शर्मा पर सस्पेंस खत्म करें शुभमन गिल

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को 2027 वनडे विश्व कप में खेलते देखने की इच्छा सिर्फ भारतीय प्रशंसकों की ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की है। 2023 विश्व कप में अपनी कप्तानी में भारत को फाइनल तक पहुंचाने वाले रोहित आज भी वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए वनडे मुकाबले में शानदार शतक लगाकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनका बल्ला अब भी उतना ही प्रभावी है। इस प्रदर्शन के बाद वह आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या चयनकर्ता उन्हें 2027 विश्व कप तक टीम का हिस्सा बनाए रखेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर चल रही सभी चर्चाओं पर अब विराम लगना चाहिए। उन्होंने भारतीय

वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को सलाह देते हुए कहा कि अगर वह चाहते हैं कि रोहित 2027 विश्व कप टीम का हिस्सा बनें, तो उन्हें खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए।

कैफ ने कहा कि टीम के कप्तान की राय चयन प्रक्रिया में बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में शुभमन गिल को मीडिया के सामने आकर स्पष्ट कहना चाहिए कि वह 2027 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा को अपनी टीम में देखना चाहते हैं। इससे खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और प्रशंसकों के बीच बना भ्रम भी खत्म हो जाएगा।

अनुभव-फॉर्म दोनों हैं रोहित की सबसे बड़ी ताकत

रोहित शर्मा का अनुभव और बड़े टूर्नामेंटों में प्रदर्शन भारत के लिए हमेशा अहम रहा है। उन्होंने कई बार दबाव भरे मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई है। मौजूदा समय में उनका फॉर्म भी शानदार नजर आ रहा है, जिससे यह बहस और तेज हो गई है कि उन्हें 2027 विश्व कप तक मौका मिलना चाहिए। अब सभी की निगाहें कप्तान शुभमन गिल, टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं के अगले फैसले पर टिकी हैं। यदि गिल खुलकर रोहित के समर्थन में सामने आते हैं, तो इस पूरे मामले पर चल रहा सस्पेंस काफी हद तक खत्म हो सकता है।

टीम इंडिया छोड़ते ही केकेआर में बड़ा प्रमोशन

गौतम गंभीर के भरोसेमंद रयान टेन डोशेट को मिली टीम की नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक प्रशिक्षक पद से इस्तीफा देने के महज 24 घंटे बाद ही रयान टेन डोशेट ने अपने करियर की नई और बड़ी पारी शुरू कर दी है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पूर्व खिलाड़ी और प्रशिक्षक रहे टेन डोशेट को अब नाइट राइडर्स समूह ने क्रिकेट रणनीति प्रमुख नियुक्त किया है। यह केवल नई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनके क्रिकेट करियर का अब तक का सबसे बड़ा पदोन्नयन माना जा रहा है। 45 वर्षीय टेन डोशेट अब केवल एक टीम नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक क्रिकेट नेटवर्क की रणनीति, प्रतिभा खोज और खिलाड़ियों के विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे।

बीसीसीआई का प्रस्ताव ठुकराया, परिवार को दी प्राथमिकता

एक दिन पहले ही टेन डोशेट ने भारतीय टीम के सहायक प्रशिक्षक पद से इस्तीफा दिया था। जानकारी के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया। करीब दो वर्षों तक लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में व्यस्त रहने के बाद उन्होंने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। हालांकि, क्रिकेट से उनका यह विराम केवल 24 घंटे का ही रहा। नई जिम्मेदारी में टेन डोशेट नाइट राइडर्स समूह की सभी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए क्रिकेट की दीर्घकालिक योजना तैयार करेंगे। उनके प्रमुख कार्यों में खिलाड़ियों की खोज और चयन, टीम गठन, प्रदर्शन का विश्लेषण, युवा खिलाड़ियों के विकास की योजना तथा सभी विदेशी टीमों के क्रिकेट संचालन की निगरानी शामिल होगी।

वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टीम चैंपियनशिप

भारत की पुरुष-महिला टीम ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट

ओंटारियो। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष टीम ने प्री-क्वार्टर फाइनल में कुवैत को 2-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने ग्रुप चरण के अपने अंतिम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से मात देकर नॉकआउट दौर में दमदार अंदाज में कदम रखा। पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय पुरुष टीम को कुवैत के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मुकाबले के पहले मैच में भारत के युशा नफीस को कुवैत के अब्दुल्ला अली के हाथों सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीय टीम शुरुआती दबाव में आ गई। हालांकि, दूसरे मुकाबले में आर्यवीर दीवान ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खालिद वलीद अल फौजैन को 11-5, 11-6 और 11-5 से हराकर मुकाबला 1-1 से बराबरी पर ला दिया। इसके बाद निर्णायक मुकाबले में गुरवीर सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब्दुल रहमान अल सानिया को 11-3, 11-3 और 11-4 से हराकर भारत को 2-1 की महत्वपूर्ण जीत दिलाई।

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

गिल फिर बने वनडे के बादशाह, 15 साल के सूर्यवंशी ने रैंकिंग में मचाई सनसनी

दुबई। **आईसीसी की जारी ताजा रैंकिंग** में भारतीय क्रिकेट का दबदबा देखने को मिला है। भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में शानदार छलांग लगाकर क्रिकेट जगत में अपनी पहचान और मजबूत कर ली है।

जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में भारत की 3-0 की शानदार जीत का फायदा भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग में भी मिला है। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने ताजा टी20 रैंकिंग में 230 स्थानों की बड़ी छलांग लगाई है। वैभव अब टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की सूची में 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में 536 रेटिंग अंक हैं, जो उनके

करियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में वैभव ने 50.33 की शानदार औसत से 151 रन बनाए थे। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब भी मिला था।

ईशान नंबर-1 पर कायम, तिलक और श्रेयस को फायदा

टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन का दबदबा बरकरार है। वह 910 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं। वहीं, तिलक वर्मा ने दो स्थान की छलांग लगाकर छठे नंबर पर जगह बना ली है। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार सुधार करते हुए सात पायदान की छलांग लगाई और अब वह 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को बड़ा फायदा हुआ है। जिम्बाब्वे सीरीज में तीन विकेट लेने के बाद उन्होंने टी20 रैंकिंग में 31 स्थान की लंबी छलांग लगाई और अब वह 41वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

मनोरंजन | **बॉलीवुड का कोना**

कारवां में घुसा असिस्टेंट डायरेक्टर, दंग रह गईं अभिनेत्री काजल ने सुनाया चौंकाने वाला किस्सा

अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपने फिल्मी करियर से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। काजल ने बताया कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्हें कई तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, लेकिन हर मुलाकात सुखद नहीं रही। उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र किया, जब एक असिस्टेंट डायरेक्टर बिना अनुमति उनके कारवां में घुस आया और ऐसा व्यवहार किया, जिससे वह पूरी तरह घबरा गईं। काजल अग्रवाल के मुताबिक, यह घटना उस समय की है जब वह एक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद अपने कारवां में आराम कर रही थीं। तभी फिल्म की टीम में शामिल एक असिस्टेंट डायरेक्टर अचानक बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गया। इसके बाद उसने अपनी शर्ट उतार दी और अपनी छाती पर बना काजल के नाम का टैटू दिखाने लगा। अभिनेत्री ने बताया कि यह सब इतना अचानक हुआ कि वह कुछ पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा कि इस घटना के दौरान उनके हाथ-पैर कांपने लगे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए।

फैन होना अलग, मर्यादा रखना जरूरी | काजल ने माना कि उस व्यक्ति ने उनके नाम का टैटू बनवाकर अपनी दीवानगी जरूर दिखाई, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह गलत था। उन्होंने कहा कि किसी महिला के निजी स्थान में बिना अनुमति प्रवेश करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रशंसक क्यों न हो, उसे अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। काजल ने उस असिस्टेंट डायरेक्टर को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।

सेलिब्रिटी की निजता का सम्मान जरूरी

काजल अग्रवाल का कहना है कि कलाकारों को भी अपनी निजी जिंदगी और सुरक्षा का पूरा अधिकार है। उन्होंने इस घटना के जरिए यह संदेश दिया कि प्रशंसकों को अपने पसंदीदा सितारों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए और किसी भी तरह की ऐसी हरकत से बचना चाहिए, जिससे सामने वाले को असहज या असुरक्षित महसूस हो। वर्क फ्रंट की बात करें तो काजल अग्रवाल जल्द ही फिल्म रामायण में मंथरा के अहम किरदार में दिखाई देंगी। हिंदी सिनेमा में उन्हें अजय देवगन के साथ सिंघम और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में निभाए गए दमदार किरदारों के लिए खास पहचान मिली है।

52 साल के राम कपूर ने पार की मर्यादा? 22 साल छोटी श्रेया कालरा को किया किस, पत्नी ने मांगी माफी

रियलिटी शो लॉक अप अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और फिनाले से पहले शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। फैमिली वीक के दौरान सभी कंटेस्टेंट्स के घरवाले और करीबी उनसे मिलने पहुंचे। इस मुलाकात में जहां कई भावुक पल देखने को मिले, वहीं कुछ रिश्तों की तल्खियां भी खुलकर सामने आ गईं। कई फैमिली मेंबर्स ने अपने-अपने प्रिय कंटेस्टेंट्स का पक्ष लिया तो कुछ ने दूसरे प्रतिभागियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इस एपिसोड का सबसे चर्चित पल तब आया जब टीवी अभिनेता राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर शो में पहुंचीं। उन्होंने कंटेस्टेंट श्रेया कालरा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। दरअसल, शो के दौरान श्रेया कई बार राम कपूर के व्यवहार पर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि राम कपूर का बार-बार उन्हें किस करना और जरूरत से ज्यादा टची होना उन्हें पसंद नहीं आया।

इसी मुद्दे पर गौतमी कपूर ने श्रेया से कहा, अगर इन्होंने आपको गलत तरीके से छुआ है, अगर इन्होंने आप पर थूका है, तो मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूं।गौतमी के इस बयान ने शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स को चौंका दिया और यह पल सोशल मीडिया पर भी

चर्चा का विषय बन गया। फैमिली वीक में श्रेया कालरा के बॉयफ्रेंड ऋषभ भी शो में पहुंचे। उन्होंने आकांक्षा चौधरी पर जमकर गुस्सा निकाला। ऋषभ ने आरोप लगाया कि आकांक्षा ने श्रेया के साथ बेहद गलत व्यवहार किया और उनके खाने में पानी डालकर उनका अपमान किया। गुस्से में ऋषभ ने कहा, तुमने उसके खाने में पानी डाला, उससे बदतमीजी की। इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो?÷ दोनों के बीच हुई तीखी बहस ने एपिसोड का माहौल और भी गर्म कर दिया।

मेट्रो बाजार

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जून में मजबूत रही, घरेलू मांग का मिल रहा फायदा: रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि और मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर जून में सालाना आधार पर 7.3 प्रतिशत रही है। यह जानकारी बुधवार को जारी रिपोर्ट में दी गई। केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया, वैश्विक अनिश्चितता के समय में भी भारत के बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहा है और वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सामानों के निर्यात में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मजबूत घरेलू मांग भी एक अहम कारक बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन अधिकांश सेक्टरों में मजबूत रहा, हालांकि खनन और उत्खनन क्षेत्र इसमें अपवाद रहा। जून में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर बढ़कर 7.8 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 5.2 प्रतिशत थी। इस दौरान विनिर्माण के 23 में से 19 उप-क्षेत्रों ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इलेक्ट्रिकल उपकरण क्षेत्र में 34 प्रतिशत और मोटर वाहन, ट्रेलर एवं सेमी-ट्रेलर क्षेत्र में 17.5 प्रतिशत की दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, कपड़ा क्षेत्र में 13.7 प्रतिशत, खाद्य उत्पाद क्षेत्र में 10.8 प्रतिशत और अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पाद क्षेत्र में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 14.2 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तुओं का 9.3 प्रतिशत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं का 7.7 प्रतिशत, बुनियादी ढांचा एवं निर्माण सामग्री का 7.5 प्रतिशत और प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन 4.9 प्रतिशत बढ़ा।

बैंकों की लूट का खुलासा!

चार साल में ग्राहकों से वसूले 26 हजार करोड़ से ज्यादा के न्यूनतम बैलेंस शुल्क

नई दिल्ली। देश के बैंकों द्वारा खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहकों से वसूले गए शुल्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2026 के बीच चार वर्षों में बैंकों ने न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए नहीं रखने के कारण ग्राहकों से 26,170 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी। आंकड़ों के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों ने इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक राशि ग्राहकों से वसूली है।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, केवल वित्त वर्ष 2026 में ही बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस शुल्क के रूप में 7,086.63 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें निजी बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। निजी क्षेत्र के बैंकों ने 4,948.71 करोड़ रुपए वसूले, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2,137.92 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की। आंकड़ों से साफ है कि निजी बैंकों द्वारा वसूली गई रकम सरकारी बैंकों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा रही।

निजी बैंकों में एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में सबसे अधिक 1,798.14 करोड़ रुपए न्यूनतम बैलेंस शुल्क के रूप में वसूले। वहीं, एक्सिस बैंक ने 1,081.33 करोड़ रुपए की वसूली की। इन दोनों बैंकों की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूले गए कुल शुल्क का करीब 58 प्रतिशत रही। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने 353.50 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक ने 290.65 करोड़ रुपए, यस बैंक ने 195.05 करोड़ रुपए और आईडीबीआई बैंक ने 175.15 करोड़ रुपए वसूले।

कटनी में देश का सबसे लंबा रेल ग्रेड सेपरेटर तैयार

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत कटनी में निर्माणाधीन देश के सबसे लंबे रेल ग्रेड सेपरेटर (रेल फ्लाईओवर) को वर्ष 2026 के अंत तक परिचालन के लिए तैयार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित की जा रही 33.40 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। रेलवे ने नवंबर तक शेष निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, ताकि वर्षांत तक पूरे ग्रेड सेपरेटर पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सके। करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत से कटंगी खुर्द से न्यू मझगवां तक विकसित हो रही इस परियोजना में 15.85 किलोमीटर लंबा अप ट्रैक पहले ही चालू किया जा चुका है। इस ट्रैक पर वर्तमान में प्रतिदिन 20 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन हो रहा है। वहीं, 17.52 किलोमीटर लंबे डाउन ट्रैक का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वायडक्ट आधारित यह डाउन ट्रैक भारतीय रेलवे की सबसे लंबी एलिवेटेड रेल संरचनाओं में शामिल होगा।

UDISE+ रिपोर्ट का खुलासा: सात राज्यों में 65% सिंगल-टीचर स्कूल

देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, आंध्र प्रदेश सबसे आगे

नई दिल्ली. एजेंसी

देश की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। UDISE+ 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 1,00,843 स्कूल ऐसे हैं, जहां पूरी व्यवस्था सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रही है। सबसे ज्यादा ऐसे स्कूल आंध्र प्रदेश में हैं, जहां 16,357 विद्यालयों में केवल एक शिक्षक तैनात है।

रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड में 9,827, महाराष्ट्र में 9,269, कर्नाटक में 8,042, उत्तर प्रदेश में 7,874, राजस्थान में 7,200 और पश्चिम बंगाल में 6,769 सिंगल-टीचर स्कूल हैं। इन सात राज्यों में देश के कुल ऐसे स्कूलों का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा है।

शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में शिक्षकों की स्थिति से जुड़े सवाल के जवाब में ये आंकड़े साझा किए। हालांकि, रिपोर्ट में सभी प्रबंधन वाले स्कूल शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि शिक्षकों की भर्ती, नियुक्ति और तैनाती की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होती है। केंद्र सरकार ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्यों को पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी जाती है। साथ ही शिक्षकों की जरूरत का आकलन करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात तय मानकों के भीतर है, लेकिन सिंगल-टीचर स्कूलों के आंकड़े बताते हैं कि कई क्षेत्रों में शिक्षकों की

छोटे राज्यों में भी बनी हुई है समस्या

सिंगल-टीचर स्कूलों की समस्या केवल बड़े राज्यों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में 4,793, तमिलनाडु में 3,957 और असम में 3,159 ऐसे स्कूल हैं। हिमाचल प्रदेश में 3,128, उत्तराखंड में 2,655 और छत्तीसगढ़ में 2,461 स्कूल एक शिक्षक के सहारे संचालित हो रहे हैं। वहीं केरल में 67, नागालैंड में 35, सिक्किम में 31, लद्दाख में 28, दिल्ली में सात और अंडमान-निकोबार में एक ऐसा स्कूल दर्ज किया गया है। इससे साफ है कि शिक्षकों की कमी देश के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में मौजूद है। मंत्रालय के अनुसार देश में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तय मानकों के अनुसार है। प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 17, माध्यमिक स्तर पर 15 और उच्च माध्यमिक स्तर पर 23 है। इसके बावजूद एक लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक होना स्थानीय स्तर पर गंभीर चुनौती को दर्शाता है। मंत्रालय ने बताया कि शिक्षकों के खाली पदों के पीछे रिटायरमेंट, इस्तीफे, नए पदों का सृजन और छात्र संख्या में बदलाव जैसे कारण हैं। केंद्र ने राज्यों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने और शिक्षकों की जरूरत का सही आकलन करने की सलाह दी है।

इन राज्यों में सबसे ज्यादा सिंगल-टीचर स्कूल

देश में एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों की संख्या में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। यहां 16,357 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। इसके बाद झारखंड में 9,827 और महाराष्ट्र में 9,269 ऐसे विद्यालय हैं। कर्नाटक में 8,042, उत्तर प्रदेश में 7,874, राजस्थान में 7,200 और पश्चिम बंगाल में 6,769 स्कूल इस श्रेणी में आते हैं। आंकड़ों के अनुसार इन सात राज्यों में देश के कुल सिंगल-टीचर स्कूलों का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है। यह स्थिति बताती है कि बड़े राज्यों में शिक्षकों की तैनाती और जरूरत के बीच अभी भी बड़ा अंतर मौजूद है।

गुजरात के जामनगर का मामला

शराब में जहर देकर की पति की हत्या फैक्ट्री में 15 फीट नीचे दफनाई लाश

अहमदाबाद. एजेंसी

गुजरात के जामनगर में 2 साल पहले लापता हुए युवक की हत्या का सनसनीखेज और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर की थी। मृतक को शराब में साइनाइड मिलाकर पिलाया और फिर शव को 15 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या था पूरा मामला

मृतक का नाम जिग्नेश धर्मेशभाई मावदीया है। 2 साल पहले सिटी क्रपुलिस स्टेशन में जिग्रेश के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी और नीलेश मनसुखभाई कचेटिया के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों ने मिलकर जिग्नेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची।

दबाव बनाने पर खुला राज

मृतक के भाई अशोक मावदीया ने जिग्नेश से बात करने की जिद की। जब उसने भाभी से पुलिस के पास जाने को कहा तो वह डर गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पूरी साजिश का खुलासा हुआ। आरोपियों के बताए अनुसार पुलिस ने दरेड की फैक्ट्री में खुदाई शुरू की। फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में इंसानी शरीर के अवशेष निकाले गए। पुलिस ने पृथ्वी और प्रेमी नीलेश कचेटिया के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अवशेषों की साइंटिफिक जांच के बाद आगे सबूत जुटाए जाएंगे।

शराब में साइनाइड मिलाकर पिलाया

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने जिग्नेश को शराब में साइनाइड मिलाकर पिला दिया। इससे उसकी मौत हो गई। फिर सबूत मिटाने के लिए शव को दरेड इलाके की एक किराए की फैक्ट्री में लेकर गए और 12 से 15 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। पति की हत्या के बाद पत्नी पृथ्वी परिवार को बताती रही कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने गया है। उसने कहा कि जिस कंपनी में वह काम करता है वहां मोबाइल रखने की इजाजत नहीं है। इसी बहाने से उसने करीब 2 साल तक परिवार को गुमराह किया।

कर्नाटक हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार

अवैध प्रवासियों को खुश करना बंद करें, खतरे में देश की सुरक्षा

बेंगलुरु. एजेंसी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। यह मामला बेंगलुरु के एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। यह एफआईआर तब दर्ज की गई थी जब उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को एक संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी प्रवासी की पहचान करने में मदद की थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब जांच अधिकारी ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) को संदिग्ध अवैध प्रवासी के बारे में जानकारी दी तो उसके कुछ ही मिनटों बाद उस विदेशी नागरिक के आरोपों के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि यह एफआईआर बदले की भावना से की गई जवाबी कार्रवाई (काउंटर-

ब्लास्ट) के अलावा और कुछ नहीं थी।रिकॉर्ड की जांच करते हुए जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने पाया कि जांच अधिकारी ने सुबह 11:30 बजे एफआरआरओ को पत्र लिखकर संदिग्ध अवैध प्रवासी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था, जबकि याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर सुबह 11:45 बजे दर्ज की गई थी। घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए जज ने टिप्पणी की, 'यह सीधे तौर पर जवाबी कार्रवाई (काउंटर-ब्लास्ट) है।' जज ने बार-बार पूछा कि एफआरआरओ को जानकारी देने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही मारपीट का आरोप लगाने वाली एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है।

यह खतरनाक सिस्टम है, देश की सुरक्षा खतरे में है

कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, 'इसी वजह से ये अवैध प्रवासी यहां बने रहते हैं। अगर सरकार उन्हें इस तरह सपोर्ट करेगी तो ऐसा ही होगा। कोर्ट ने आगे कहा, अगर सिस्टम ऐसी चीजों को सपोर्ट करता है तो अवैध प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। यह सिस्टम के लिए खतरनाक है। देश की सुरक्षा खतरे में है। जज ने सवाल किया कि जब जांच अधिकारी ने खुद संदिग्ध अवैध प्रवासी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी तो शिकायतकर्ता के खिलाफ ही आपराधिक मामला क्यों दर्ज किया गया।

तंत्र-मंत्र के चलते बच्चे की मौत के बाद संचालक-सेवादारों को पीटा

काशीपुर. एजेंसी

तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के दौरान छह वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। शिवलालपुर अमरझंडा स्थित एक धाम में हुई घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने संचालक और सेवादारों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद वे धाम संचालक सत्यवीर और एक सहयोगी को अपने साथ ले गए और चंदौसी पहुंचकर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद निवासी सत्यवीर सिंह ने सात साल पहले शिवलालपुर अमरझंडा में धाम की स्थापना की थी। यहां हर मंगलवार को दरबार लगता है, जहां तंत्र-मंत्र, ऊपरी बाधा और कई बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है।

कीर्ति कुल्हारी हुईं साइबर फ्रॉड की शिकार, लाखों की ठगी के बाद पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत

नई दिल्ली. एजेंसी

अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी के साथ साइबर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अज्ञात अपराधियों ने उनके मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड का अनधिकृत एक्सेस हासिल कर महज कुछ ही मिनटों में 2,43,852 रुपए का फ्रॉड किया है। अभिनेत्री की शिकायत पर अंबोली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर के मुताबिक इस मामले में कीर्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में बताया गया है कि कीर्ति के साथ साइबर ठगी रात के समय लगभग 9:31 बजे हुई थी। उस समय वह अंधेरी पश्चिम में फन रिपब्लिक मॉल के पास स्थित सिनेपोलिस थिएटर में थीं। इसी दौरान उनके मोबाइल नंबर पर बैंक के क्रेडिट कार्ड से एयरोमेक्सिको एयरलाइन पर 2,525 अमेरिकी डॉलर खर्च होने का अलर्ट मैसेज मिला।अनजान और संदिग्ध विदेशी लेनदेन का मैसेज देखते ही अभिनेत्री ने बिना समय गंवाए बैंक के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। बैंक अधिकारियों ने जांच के बाद बताया कि उनके क्रेडिट कार्ड से बिना अनुमति के ट्रांजैक्शन किए गए हैं।

दोपहर मेट्रो

ग्रामीण इंटरनेट पहुंच और डिजिटल ढांचे में भी सुधार हुआ

एक दशक में भारत से मोबाइल फोन का निर्यात 165 गुना बढ़ा

नई दिल्ली. एजेंसी

सरकार ने संसद में बताया कि पिछले एक दशक में भारत के मोबाइल फोन निर्यात में 165 गुना बढ़ोतरी हुई है। यह 2014-15 के लगभग 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में लगभग 2.59 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो देश के वैश्विक इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर तेजी से उभरने का प्रमाण है।

लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोबाइल फोन का उत्पादन भी लगभग 33 गुना बढ़ा है और यह 2014-15 के 18,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 6.27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन लगभग सात गुना बढ़ा है और यह 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 13.11

लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगभग 11 गुना बढ़ा और यह लगभग 38,000 करोड़ रुपये से 4.24 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

मोबाइल उत्पादन ईकोसिस्टम में 96 हजार करोड़ का निवेश बढ़ाया

सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि पीएलआइ स्कीम ने घरेलू मोबाइल प्रोडक्शन ईकोसिस्टम में 96 हजार करोड़ रुपये का निवेश बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना-प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि सरकार की पहलों के बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 के 11.32 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पीएलआइ-एलएसईएम योजना शुरू की गई थी। मंत्री ने कहा, 'स्मार्टफोन 2014 में शीर्ष 100 निर्यात होने वाली वस्तुओं में शामिल नहीं थे, लेकिन अब ये पेट्रोलियम, रत्न और आभूषणों को पीछे छोड़कर वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुओं में शामिल हो गया है।

ग्रामीण इंटरनेट की पहुंच में सुधार हुआ

दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को संसद में बताया कि 2025-26 के दौरान देश में ग्रामीण इंटरनेट की पहुंच में सुधार हुआ है और ग्रामीण इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या प्रति 100 आबादी पर 45.03 से बढ़कर 48.31 हो गई है। सिंधिया ने कहा कि नेशनल ब्राडबैंड मिशन 2.0 के तहत, 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्राडबैंड डाउनलोड स्पीड 60.85 एमबीपीएस तक पहुंच गई। साथ ही, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ियों और पंचायत कार्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी बढ़कर 21,82,312 कनेक्शन हो गई।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा*** आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564